



जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट
जिला विकास योजना के साथ
का
आकांक्षी जिला नर्मदा
2020 – 21

द्वारा तैयार :

एमएसएमई-विकास संस्थान
अहमदाबाद
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
हरसिद्ध चेम्बर्स, चौथी मंजिल,
आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014
फोन: 079-27543147/27544248
ई-मेल: dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
वेबसाइट: www.msmediaahmedabad.gov.in

अग्रेषित

किसी भी विकासशील राष्ट्र की वर्तमान अर्थव्यवस्था विश्व आर्थिक संघ और विकसित राष्ट्र की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के साथ प्रचलित संबंधों पर निर्भर करती है। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील राष्ट्र की अवधारणा के किनारे से गुजर रही है। वर्तमान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और अनुमानित विकास दर प्राप्त करने के लिए, औद्योगीकरण के विकास को बढ़ाना होगा। जनसंख्या विस्फोट सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि और उद्योगों में अनुमानित दर पर अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती है।

2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने नर्मदा को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक नाम दिया। नर्मदा जिला वडोदरा और बारूच जैसे अच्छी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित जिले के बहुत करीब है जहां एमएसएमई की अच्छी एकाग्रता है, और कई एमएसएमई विस्तार या विविधीकरण की तलाश में हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए नर्मदा जिले में अपनी अन्य इकाइयां स्थापित करने के लिए एमएसएमई को आकर्षित करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे वे वहां पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू कर सकें। जिले की ताकत वहां के श्रमिकों की उपलब्धता है, जो वडोदरा और बारूच में प्रवास करते हैं, तथा रेल और सड़क से गुजरात के अन्य शहरों से सीधा संपर्क भी। जिले में वन उपज का प्रसंस्करण भी एक अप्रयुक्त क्षमता है।

जिले में मौजूद संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं का उपयुक्त और आवश्यक डेटा बेस पूरे राज्य के अनुरूप जिले के सभी क्षेत्रों के विकास और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को तैयार करने में मदद करता है। साथ ही, उद्यमशीलता को बढ़ाने और नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों और औद्योगिक सेमिनारों आदि के माध्यम से स्थानीय लोगों की दक्षता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह जिले में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा।

एमएसएमई-विकास संस्थान नियमित अंतराल पर जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में औद्योगिक जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ढांचागत सुविधाओं, कुशल मानव शक्ति, बाजार की स्थितियों आदि पर संसाधनपूर्ण डेटा उपलब्ध कराता है।

एमएसएमई-विकास संस्थान, अहमदाबाद के श्री पी.एन. सोलंकी, आईईडीएस, उप. निदेशक, श्री ए. जे. परमार, आईएसएस, सहायक निदेशक, श्री पी.एल.शाह, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और श्री एस.डी.रमावत अन्वेषक (ई/आई)के महत्वपूर्ण प्रयासों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से एकत्रित विभिन्न महत्वपूर्ण और उपयोगी आंकड़ों और सूचनाओं का उपयोग करके नर्मदा जिले की जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट तैयार की है। मैं सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों आदि का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना सहयोग दिया है।

अहमदाबाद

30.06.2021

(विकास गुप्ता)

संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रभारी

अंतर्वस्तु

अध्याय क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं
1.	कार्यकारी सारांश परिचय	01
2.	परिचय	02
3.	जिला एक नजर में	03-06
4.	संसाधनों का विश्लेषण	07-23
5.	औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना	24-39
6.	वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य	40-42
7.	नए एमएसएमई/औद्योगिक विकास की संभावनाएं	43-47
8.	योजनाएं और हस्तक्षेप	48-52
9.	आत्म निर्भर भारत आंदोलन आत्मानिभर भारत के पांच स्तंभों के नीचे	53-54
10.	जिला औद्योगिक विकास योजना	55
11.	किससे संपर्क करें और किसलिए?	56-57
12.	सारांश और निष्कर्ष	58
13.	जिले में संसाधनों की सूची	59-61

अध्याय : 1

कार्यकारी सारांश

नर्मदा जिला देश के पहचाने गए जिले के साथ-साथ आकांक्षा जिले में से एक है। जिले की प्रमुख भूमि आरक्षित वन है, जो 44% से अधिक है और अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी है। चूंकि वन आरक्षित है, इसलिए किसी भी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसलिए, जिलों में एमएसएमई सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रमुख केंद्रीकरण नहीं है। जिले की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां एक खेती है प्रमुख फसलें धान और अनाज के अलावा अन्य कृषि उत्पादों के साथ केले के फल हैं।

वर्तमान में केला, केवल किसानों द्वारा बेचा जा रहा है, लेकिन केले की भाप की तरह छोड़ दिया गया है, फाइबर, एसएपी पानी और बचे हुए पदार्थ जैसे उत्पादों के उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है जो बहुत अच्छा अवशोषक है और सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है और यदि केला स्टेम का उपयोग जिले की औद्योगिक तस्वीर को बदल सकता है और इस आकांक्षा जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

जिले के प्रमुख स्थल हैं सरदार सरोवर परियोजना - नर्मदा बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पर्यटन स्थल है। पर्यटन उद्योगों को पूरा करने के लिए, एमएसएमई को नर्मदा बांध स्थल के **आसपास** और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के **आसपास** उत्पादों/सेवा जैसे भोजन, परिधान निर्माण, लिनन, कपड़ा, कपड़े धोने आदि के लिए स्थापित किया जा सकता है।

नर्मदा जिला वडोदरा और भरूच जैसे अच्छी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित जिले के बहुत करीब है जहां एमएसएमई की अच्छी एकाग्रता है, और कई एमएसएमई विस्तार या विविधीकरण की तलाश में हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए नर्मदा जिले में अपनी दूसरी इकाई स्थापित करने के लिए एमएसएमई को आकर्षित करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है, जो बदले में औद्योगिक गतिविधि शुरू करेगा। जिले की ताकत श्रमिकों की उपलब्धता है, जो वडोदरा और भरूच में प्रवास करते हैं, और अच्छी तरह से रेल और सड़क संपर्क है। जिले में वन उपज का प्रसंस्करण भी एक अप्रयुक्त क्षमता है।

अध्याय : 2

परिचय :

जिला औद्योगिक विकास योजना तथा "आत्मनिर्भर भारत" की अवधारणा के साथ आकांक्षी जिला-नर्मदा की जिला औद्योगिक संभावित सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीआईपीएस): 2020-21 को लाइन में तैयार किया गया है जिसे तैयार करने के लिए जिले के आर्थिक विकास को समर्थन और मजबूत करने के लिए जिले में काम कर रहे गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों से एकत्रित विभिन्न संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं को संकलित किया गया है।

कार्यप्रणाली :

सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में जिले में स्थित विभिन्न राज्य सरकार के कार्यालयों, स्थानीय निकायों आदि से एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से डेस्क सर्वेक्षण, डेटा का प्रलेखन, विभिन्न विभागों और संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में शामिल व्युत्पत्तियां और संकलन शामिल हैं। "माध्यमिक" के साथ-साथ "प्राथमिक" डेटा के समवर्ती महत्व और स्थानीय बाजारों, मांग, कृषि और औद्योगिक संचालन और वित्तीय प्रणाली आदि जैसे महत्वपूर्ण रूपों के बारे में जानकारी

उद्देश्य :

जिला औद्योगिक संभावित सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीआईपीएस) का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में जिले में स्थानीय संसाधनों और मांग के आधार पर नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और विकास की संभावनाओं का पता लगाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कच्चे माल, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी ढांचे, आर्थिक क्षेत्र को मौद्रिक सहायता, औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों के सही अनुमानों को महत्वपूर्ण महत्व देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में वर्तमान एसएमई क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई है ताकि नए लोग इसे दूर कर सकें और विकास की लक्षित दर हासिल करने में सफल हो सकें। रिपोर्ट केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के बजाय तकनीकी-आर्थिक प्रकृति की है। यह एक केंद्रित मार्गदर्शक होगा और जिले के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इसका उचित प्रचार किया जाएगा।

दायरा :

यह रिपोर्ट तुलनात्मक रूप से उच्च औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार की गई है। इसने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है और आने वाले वर्षों में लक्षित औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए विनम्र प्रयास किए गए हैं।

अध्याय : 3

जिला : एक नजर

("आत्मनिर्भर भारत" की अवधारणा के अनुरूप ")

भौतिक और भौगोलिक विशेषताएं :

नर्मदा जिला गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा करता है और दक्षिण में सूरत, उत्तर में वडोदरा और पश्चिम में भरूच से घिरा है।

नंदोद तालुका में स्थित राजपिपला अन्य तालुका के साथ सरकारी प्रशासन के लिए जिला मुख्यालय है, जैसे डेडियापाड़ा, सागबारा और जिले में कुल 5 तालुका, 5 कस्बे और 615 गाँव हैं। राजपिपला शहर जिले का प्रमुख औद्योगिक शहर है। निवेश की आगे की संभावनाओं के लिए केंद्रित औद्योगिक क्षेत्र कपड़ा, कृषि खाद्य उद्योग और रसायन, शीत भंडारण, होटल और जड़ी-बूटी है।

जिला एक नजर में :

क्रम.	विवरण	इकाई	आंकड़े
1	भौगोलिक विशेषताओं		
(अ)	भौगोलिक डेटा		
	1) अक्षांश	उत्तर	21.24' से 22.0'
	2) देशांतर	पूर्व	72.4' से 73.14'
	3) भौगोलिक क्षेत्र	हेक्टेयर	2,74,436
(ब)	प्रशासनिक इकाइयाँ		
	1) उप प्रभाग	संख्या	--
	2) तहसीलें	संख्या	04
	3) उप-तहसील	संख्या	0
	4) पटवारी सर्कल	संख्या	0
	5) पंचायत समितिस	संख्या	18
	6) नगर निगम	संख्या	0
	7) नगर पालिका	संख्या	04
	(8) ग्राम पंचायतें	संख्या	222
	(9) राजस्व गांव	संख्या	614
	(10) विधानसभा क्षेत्र	संख्या	2
2.	जनसंख्या		
(अ)	लिंग		
	1 पुरुष	संख्या	3,01,086
	2 महिला	संख्या	2,89,211
	कुल योग :		4,90,297
(ब)	ग्रामीण आबादी	संख्या	4,28,424

3.	कृषि		
	भूमि उपयोग		
	1 कुल क्षेत्रफल	हेक्टेयर	2,91,023
	2 वन आवरण	"	1, 14,709
	3 परती भूमि	"	7,600
	4 खेती योग्य बंजर भूमि	"	4,400
	5 शुद्ध बोया गया क्षेत्र	"	1,13,000
4.	वन	"	
	(1) वन	हेक्टेयर	1, 14,709
5.	पशुधन और कुक्कुट		
क	पशु	संख्या	2,43,671
	1) गाय	संख्या	1,74,647
	2) भैंस	संख्या	79,014
ख	अन्य पशुधन		
	1) बकरियां	संख्या	79,827
	2) सुअर	संख्या	183
	3) कुत्ते और कुतिया	संख्या	367
	4) रेलवे		
	(1) रेल लाइन की लंबाई	किमी.	18
	(2) सड़कें		
	(अ) राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी.	92.00
	(ब) राज्य राजमार्ग	किमी.	286.60
	(स) मुख्य जिला राजमार्ग	किमी.	184.30
	(द) अन्य जिला और ग्रामीण	किमी.	234.38
	(य) ग्रामीण सड़क / कृषि मार्केटिंग बोर्ड रोड्स	किमी.	1308.30
	(र) कच्चे रोड	किमी.	139.00
	(6) संचार		
	(अ) टेलीफोन कनेक्शन	संख्या	4434
	(ब) डाकघर	संख्या	140
	(स) टेलीफोन केंद्र	संख्या	03
	(द) टेलीफोन का घनत्व	संख्या/1000 व्यक्ति	70
	(य) टेलीफोन का घनत्व	संख्या प्रति किमी	17
	(7) सार्वजनिक स्वास्थ्य		
	(क) एलोपैथिक अस्पताल	नहीं	18
	(ख) एलोपैथिक अस्पतालों में बिस्तर	नहीं	494
	(ग) आयुर्वेदिक अस्पताल	नहीं	न
	(ड़) आयुर्वेदिक अस्पताल में बिस्तर	नहीं	न
	(च) यूनानी अस्पताल	नहीं	न
	(छ) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	नहीं	04
	(ज) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	नहीं	28
	(झ) औषधालय	नहीं	न
	(ञ) उप स्वास्थ्य केंद्र	नहीं	134

	(ट) निजी अस्पताल	नहीं	20
	(8) बैंकिंग व्यावसायिक		
	(क) वाणिज्यिक बैंक	संख्या	38
	(ख) ग्रामीण बैंक उत्पाद	संख्या	07
	(ग) सहकारी बैंक उत्पाद	संख्या	14
	(घ) पीएलडीबी शाखाएं	संख्या	03
	(ङ) निजी बैंक	संख्या	10
	(9) शिक्षा		
	(1) प्राथमिक विद्यालय	संख्या	731
	(2) माध्यमिक विद्यालय	संख्या	---
	(3) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	संख्या	130
	(4) कॉलेज	संख्या	04
	(5) तकनीकी विश्वविद्यालय	संख्या	0

उद्योग आधार ज्ञापन में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या (31.03.2021 तक)

(विनिर्माण और सेवा क्षेत्र) सहित उद्यम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
सूक्ष्म	497
लघु	82
मध्यम	11
कुल	490

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या (31.03.2021 तक)

(विनिर्माण और सेवा क्षेत्र) सहित उद्यम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
सूक्ष्म	272
लघु	10
मध्यम	0

कुल	282
-----	-----

अध्याय : 4

संसाधनों का विश्लेषण

किसी भी जिले का सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास स्पष्ट रूप से प्राकृतिक और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है।

(क) मानवीय संसाधन :

यह अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर और लक्षित विकास दर प्राप्त करने में अधिक महत्व चाहता है इसलिए, इसे मुख्य रूप से कुशल और अकुशल दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रम शक्ति को अर्थव्यवस्था की मुख्य कुंजी माना जाता है। श्रम की उपलब्धता और उच्च उत्पादकता लक्षित विकास की उपलब्धियों में भारी योगदान दे सकती है। श्रम बल पूरे जिले में फैला हुआ है कुल मानव संसाधन का उपलब्ध कुशल श्रम लगभग 34.28 प्रतिशत है, जिसमें से 29.16 प्रतिशत कृषि में तथा 22.55% मुख्य श्रमिक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जनगणना के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं।

1. आबादी :

विवरण	विवरण	गुजरात राज्य	नर्मदा जिला
गांवों की संख्या	कुल योग	18,224	609
	बसे हुए	17,843	448
	निर्जन	382	41
कस्बों की संख्या	वैधानिक	194	1
	जनगणना	143	4
	कुल योग	348	4
ग्रहस्थियों की संख्या	साधारण	1,22,48,428	1,20,941
	संस्थागत	36,924	461
जनसंख्या कुल	व्यक्तियों	6,04,39,692	4,90,297
	पुरुष	3,14,91,260	3,01,086
	महिला	2,89,48,432	2,89,211
ग्रामीण	व्यक्तियों	3,46,94,609	4,28,424
	पुरुष	1,77,99,149	2,69,408
	महिला	1,68,94,440	2,49,017

शहरी	व्यक्तियों	2,47,44,083	61,872
	पुरुष	1,36,92,101	31,678
	महिला	1,20,42,982	30,194

विवरण	विवरण	गुजरात राज्य			नर्मदा जिला
प्रतिशत शहरी जनसंख्या		42.60			10.48
दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011		संख्या	%	संख्या	%
	व्यक्ति	97,68,674	19.27862	4,90,297	14.80
	पुरुष	41,04,683	19.34028	3,01,086	14.10
	महिला	46,62,992	19.20077	2,89,211	14.40
क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)		1,96,244			2,817
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		308			210
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	कुल योग	919			961
	ग्रामीण	949			961
	शहरी	880			943
साक्षरों		संख्या	%	संख्या	%
	व्यक्तियों	4,10,93,348	78.03	3,70,336	62.73
	पुरुष	2,34,74,873	84.74	3,21,677	44.49
	महिला	1,76,18,484	69.68	48,649	08.24
अनुसूचित जाति	व्यक्तियों	40,74,447	6.74	8,733	01.48
	पुरुष	21,10,331	6.70	4,464	00.76
	महिला	19,64,116	6.78	4,268	00.72
अनुसूचित जनजाति	व्यक्तियों	89,17,174	14.74	4,81,392	81.44
	पुरुष	44,01,389	14.29	2,44,424	41.42
	महिला	44,14,784	14.24	2,36,868	40.13

2. जनसंख्या का व्यावसायिक पैटर्न :

उपलब्ध श्रम शक्ति के विभिन्न पैटर्न हैं जो जिले की अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान करते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग 31.36% श्रम शक्ति उपलब्ध है। उपलब्ध श्रम शक्ति के पेशे के विभिन्न पैटर्न के अनुसार कृषि , औद्योगिक और अन्य अर्ध कुशल श्रमिकों के बीच विभाजित किया गया है ।

इसे नीचे दी गई तालिका में दिखाया जा सकता है।

विवरण	विवरण	गुजरात राज्य			नर्मदा जिला
श्रमिकों की श्रेणी (मुख्य और सीमांत)	व्यक्ति	44,47,400	22.00	46,266	09.43
(1) कृषक	पुरुष	42,44,449	23.48	46,192	08.82
	महिला	12,03,041	17.78	10,074	01.71
2) कृषि मजदूर	व्यक्ति	68,39,414	27.61	1,03,360	17.41
	पुरुष	36,49,491	20.27	68,419	11.61
	महिला	31,89,824	47.1 4	34,841	04.90
(3) घरेलू उद्योग में श्रमिक	व्यक्ति	3,43,999	01.39	1,480	00.27
	पुरुष	2,10,461	1.17	1,149	00.20
	महिला	1,33,438	1.97	421	00.07
(4) अन्य श्रमिक	व्यक्ति	1,21,36,833	49.00	32,710	04.44
	पुरुष	98,96,313	44.9 8	24,646	04.34
	महिला	22,40,420	33.11	7,064	01.20

क्रम. सं.	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1.	कल्टीवेटर	62,823	7.30
2.	कृषि श्रमिक	1,88,030	21.86
3.	घरेलू उद्यम मजदूर	2,494	0.30
4.	अन्य मजदूर	16,297	1.90
4.	कुल श्रमिक जनसंख्या	2,69,744	31.36
6.	मुख्य मजदूर	1,93,916	22.44
7.	सीमांत मजदूर	1,00,897	11.73
8.	अनुत्पादक जनसंख्या	2,94,402	34.36

	कुल जनसंख्या	8,60,049	100.00
--	---------------------	-----------------	---------------

(ख) भौतिक/शारीरिक संसाधन :

उपलब्ध विभिन्न संसाधनों जैसे तकनीकी ज्ञान, वित्त, उत्पादकता आदि का उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में तर्कसंगत उपयोग करके औद्योगिक विकास को अधिकतम किया जा सकता है।

(1) फसल पैटर्न:

जिले में शुद्ध खेती का क्षेत्र 1, 24,300 हेक्टेयर है। धान, गेहूं, बाजरा, अरहर, तंबाकू, कपास, सरसों और सौंफ प्रमुख फसलें हैं जबकि आलू, केला और नींबू भी जिले में उगाए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान जिले में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उत्पादन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	फसल का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	उत्पादन (एमटी में)
1	कपास	46884	37971.82
2	केला	9240	662332.20
3	चना	1087	991.02
4	तूर	22628	27344.99
4	मक्का	4803	8743.44
6	उड़द	809	817.41
7	सोया बीन	1833	2680.14

कृषि :

जिले में सभी मौसमों में विभिन्न फसलों की खेती नर्मदा नहर सिंचाई के माध्यम से की जाती है। नर्मदा में औसत वर्षा 1100 मिमी होती है। केला जिले का प्रमुख फल है। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और जबकि बाजरा, प्रमुख खाद्य फसलों में से हैं। कपास, ग्राउंड नट, अरंडी, और सोयाबीन प्रमुख वाणिज्यिक फसलें जिले में उगाई जाने वाली हैं। वृक्षारोपण में केला प्रमुख फसल है। इसलिए, जिले में नए फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। नर्मदा में हर्बल बॉटनिकल गार्डन है, जिसमें हर्बल पौधों की लगभग 70 प्रजातियां शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के लिए किया जाता है।

(2) कृषि योग्य भूमि का आकार

भूमि उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	भूमि का प्रकार	हेक्टेयर
1.	कृषि योग्य भूमि	124300
2.	स्थायी चारागाह भूमि	1761

3.	गैर कृषि उपयोग	31321
4.	वर्तमान परती भूमि	4973
4.	वन	114709
6.	परती भूमि	7600
7.	एक से अधिक बार खेती योग्य क्षेत्र	8744
8.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	113000
9.	कृषि योग्य अपशिष्ट	4400
10.	चारागाह जमीन	9,484

(3) कृषि विपणन:

गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जिले के सेलेम्बा, राजपिपला, देडियापाड़ा और तिलकवाड़ा तालुका में एपीएमसी बाजार स्थापित किए हैं।

एपीएमसी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	बाजार का प्रकार	सं.
1	बाजार समितियों की संख्या	04
2	मुख्य यार्डों की संख्या	04
3	उप-बाजार यार्डों की संख्या	02

कृषि आधारित उद्योगों का वर्तमान विकास:

शहद उत्पादन, किसानों द्वारा केले के चिप्स की छोटी दुकानें, उर्वरक की दुकानें और खेती के लिए छोटे उपकरण की दुकानें।

(4) सिंचाई सुविधाएं:

जल संसाधन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है (1) प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जहां खेती योग्य क्षेत्र 10000 हेक्टेयर से अधिक है, (2) मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जहां खेती योग्य क्षेत्र 2000 से 10000 हेक्टेयर के बीच है और (3) लघु सिंचाई परियोजनाएं जहां खेती योग्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है। जिले में कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए लघु सिंचाई अधिक महत्व रखती है। भूजल दोहन, जल उठाने वाले उपकरणों, लिफ्ट सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए बैंक वित्तपोषण योजनाओं के लिए मौद्रिक संस्थागत गतिविधियों पर जोर दिया जाना है। जिले की भूजल क्षमता इस प्रकार है:

क्र.सं.	तालुका का नाम	तालाब	नहरों	अन्य (चेक डैम)
1	नादोद	84	-	94
2	गरुड़ेश्वर	42	991	142
3	तिलकवाड़ा	40	-	73
4	दीदीपदा	109	90	242

4	सागबारा	80	240	210
	कुल	364	1331	762

(स्रोत: भूतपूर्व अभियंता, पंचायत सिंचाई खण्ड, राजपीपला)

गरुडेश्वर वियर :

सरदार सरोवर बांध के नीचे की ओर नर्मदा नदी पर गरुडेश्वर वियर का निर्माण, जिसकी लागत रु. लगभग 12 किमी पर 322.47 करोड़ का कार्य प्रगति पर है। । अक्टूबर-2020 तक, संशोधित निविदा मात्रा 13.31 एलसीएम के विरुद्ध 10.833 एलसीएम और 8.13 एलसीएम की संशोधित निविदा मात्रा के विरुद्ध कंक्रीट कार्य 7.70 एलसीएम है।

(5) बागवानी :

जिले में वर्ष के दौरान बागवानी में मसालों, फलों और सब्जियों का अच्छा उत्पादन होता है। आम, केला, चीकू और खरेक मुख्य फल हैं। वहीं, प्याज, आलू और ग्वार यहां की प्रमुख सब्जियां हैं। तथा जिले में ग्वार, पापड़ी, परवल पाताल आदि का उत्पादन संतोषजनक स्तर पर होता है। प्रमुख मसालों के तहत जिले में हरा धनिया, लहसुन, मिर्च और हल्दी का संतोषजनक मात्रा में उत्पादन होता है।

जिले में विभिन्न बागवानी फसलों का उत्पादन (: जिले निम्नानुसार है '1000 हेक्टेयर और में क्षेत्र में उत्पादन 1000 टन')

क्र.सं.	तालुका का नाम	फल		सब्जियां	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	नादोद	8111	491191	1218	18204
2	गरुडेश्वर	2194	144430	407	7013
3	तिलकवाड़ा	644	12008	338	3224
4	दीदीपदा	1279	10040	1467	21333
4	सागबारा	1111	13806	918	14239
	कुल योग	13340	681484	4348	64013

क्र.सं.	तालुका का नाम	मसाले		कुल	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	नादोद	110	2014	9439	411409

2	गरुड़ेश्वर	38	273	2640	16071
3	तिलकवाड़ा	11	134	1003	14366
4	दीदीपदा	79	893	2824	32276
4	सागबारा	48	616	2087	28662
	कुल योग	296	3931	17994	748428

प्रमुख खाद्य, वाणिज्यिक और वृक्षारोपण/बागवानी फसलें:

गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और बाजरा, प्रमुख खाद्य फसलों हैं कपास, ग्राउंड नट, अरंडी, और सोयाबीन प्रमुख वाणिज्यिक जिले में उगाई जाने वाली फसलें हैं। वृक्षारोपण में केला प्रमुख फसल है। इसलिए, जिले में नए फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। नर्मदा घाटों में हर्बल वानस्पतिक उद्यान, जिसमें हर्बल पौधों की लगभग 70 प्रजातियां शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के लिए किया जाता है।

(6) वन:

जिले के एक 1,14,709 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। राज्य सरकार ने वन विभाग प्राधिकरण के माध्यम से वानिकी और बंजर भूमि विकास से संबंधित विभिन्न ठोस कदम उठाए हैं। वन विभाग के पास बीज की आपूर्ति के लिए सभी तालुका में नर्सरी का नेटवर्क है। जिले में वन सामग्री का कोई उत्पादन या संग्रह नहीं है।

31/03/20 20 को तालुकावार वन क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

तालुका	कुल गांव	वन का प्रकार (हेक्टेयर में क्षेत्रफल)			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		रिज़र्व	अवर्गीकृत	संरक्षित वन	
तिलकवाड़ा	911	949.08	4.37	0	963.44
नांदोस	110	39,380.70	187.43	103.14	39,671.37
ददियापदा	97	63,776.94	487.20	14.04	64,378.19
सागबारा	92	4079.80	4188.91	10.14	9,278.86
कुल	448	1,08,196.43	4,968.01	127.33	1,14,291.87

(7) मत्स्य पालन:

मछली पालन का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	सं.
-------	-----

मत्स्य अवतरण केन्द्रों की संख्या	36
जिले में प्रत्येक मछली के लिए नावों की संख्या:	
यांत्रिक नावें	02
गैर-यांत्रिक नावें	364
समुद्री मछुआरे	शून्य
अंतर्देशीय जल मछुआरे	4,188
सक्रिय	4,881
प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों की संख्या	11
जनजातीय क्षेत्र	10
गैर-आदिवासी क्षेत्र	01
सहकारी समितियों की सदस्यता की संख्या	2673
क) जनजातीय क्षेत्र	2437
ख) गैर-आदिवासी क्षेत्र	136
सदस्यों द्वारा जमा किए गए धन को साझा करें	रु. 89646/-
जिले में कार्यरत मत्स्य आधारित उद्योगों की संख्या	शून्य

जलाशय/तालाब मात्स्यिकी का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	जलाशय का प्रकार		
	छोटा	मध्यम	बड़ा
सं.	2	1	0
हेक्टेयर	344.824.8	3,677.00	0

• नर्मदा जिले में मत्स्य विकास पर विस्तृत नोट :

जिले में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास कार्य चल रहा है। जिले के लोग छोटे भूमि धारक हैं इसलिए सांस्कृतिक और कब्जा की गई मत्स्य पालन स्थानीय स्तर की मांग और आपूर्ति के उद्देश्य तक ही सीमित है। धीरे-धीरे सहकारी समितियां सरकारी नीली क्रांति योजना का लाभ उठा रही हैं और जलाशय में युग स्थापित कर चुकी हैं।

• नर्मदा जिले में मत्स्य आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में विचार:

मत्स्य पालन के उद्देश्य से सरदार सरोवर का एक बड़ा जल निकाय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। यदि क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाता है तो इससे बड़ी संख्या में मछुआरे लाभान्वित होंगे और राजस्व भी उत्पन्न होगा। नर्मदा नदी हिल्सा और जायंट झींगे के मछली पालन लिए प्रसिद्ध है। इन प्रजातियों के अधिक उत्पादन से प्रकृति पर भार कम होगा।

- मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त मछली पकड़ने के जाल :

गिल नेट : 1092

कास्ट नेट: 600

#जिले में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में:

कतला, रोहू, मृगल, कालाबासु, ईल, झींगा, चना प्रजाति, हिलसा आदि।

(स्रोत: कार्यालय अधीक्षक मात्स्यिकी, राजपीपला)

(8) पशुपालन संसाधन :

विभिन्न का विवरण में पशुधन जिले है के रूप में नीचे दिए गए:

क्रम सं.	लाइव स्टॉक का प्रकार	कुल पशु
1.	गाय	174647
2.	भैंस	79014
3.	जहाज	442
4.	बकरी	79827
4.	घोड़े और टट्टू	69
6.	सुअर	183
7.	अन्य (गधे आदि)	974
	कुल	334266

स्रोत: पशुधन जनगणना, 2019 , नर्मदा ।

दुग्धशाला विकास :

डेयरी विकास कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों और जिले के भूमिहीन मजदूर के जीवन स्तर में सुधार के लाने के लिए कृषि क्षेत्र में संबद्ध गतिविधियों के मामले में अतिरिक्त आय सृजन के एक पूरक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण महत्व का प्रयास है।

जिले में दुग्ध सहकारी समितियों का तालुकावार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	तालुका का नाम	दुग्ध सहकारी समितियां (सं.)	दूध आपूर्ति करने वाले सदस्य।	दूध का वार्षिक संग्रह (टन में)
1	नादोद	103	4216	48.41
2	गरुड़ेश्वर	44	2784	24.38

3	तिलकवाड़ा	68	3448	60.42
4	दीदीपदा	94	3687	39.96
5	सागबारा	76	3844	30.40
	कुल योग	934	19089	204.67

(9) मिनरल आर स्त्रोत :

ग्रेवाल, बेंटोनाइट, चुनो स्टोन, ब्लैक ट्रेप, मोरम, कॉमन सैंड और कॉमन क्ले जिले में उपलब्ध लघु खनिज हैं। जिले में ब्लैक ट्रेप के लिए 20 लीज खदानें चल रही हैं।

विभिन्न प्रमुख के सांख्यिकी एवं माइनर जिले में उपलब्ध खनिज वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नानुसार है :

क्रम सं.	प्रमुख खनिज	उत्पादन (एमटी)	रॉयल्टी (रु. '000 में)
1.	बाक्साइट	0	0
2.	कार्बन	0	0
	लघु खनिज		
1.	ब्लैक ट्रेप	64824	24192868
2.	साधारण रेत	42924	1931000
3.	साधारण मिट्टी	64161	3869000
	कुल	742226	43846708

स्रोत: भूविज्ञान और खनन निदेशालय, नर्मदा ।

(10) पर्यटन :

नर्मदा जिले में पर्यटन अब बहुत विकसित हो रहा है : सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं ।

सरदार सरोवर बांध :

सरदार सरोवर बांध भारत में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास नवगाम में नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। चार भारतीय राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

ऊँचाई : 163 वर्ग मीटर

खोला गया : 17 सितंबर 2017

जलग्रहण क्षेत्र : 88,000 वर्ग किमी

सतह क्षेत्र : 374.3 वर्ग किमी
निर्माण शुरू हुआ : अप्रैल 1987
प्रमुख राज्य : गुजरात , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , राजस्थान



• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी:

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता वल्लभभाई पटेल (1875-1950) की एक विशाल प्रतिमा है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और अहिंसक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अनुयायी थे। पटेल को भारत के 562 रियासतों को पूर्व ब्रिटिश राज के एक बड़े हिस्से के साथ भारत के एकल संघ बनाने के लिए एकजुट करने में उनके नेतृत्व के लिए बहुत सम्मानित किया गया था। मूर्ति राज्य में स्थित है

भारत के। गुजरात में, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर (597 फीट) है। यह केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर (62 मील) दक्षिण-पूर्व में सरदार सरोवर बांध का सामना कर रहा है [4] और सूरत से 150 किलोमीटर (93 मील)। केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

संरचना की कुल ऊंचाई 240 मीटर (790 फीट) है, जिसका आधार 48 मीटर (190 फीट) और मूर्ति की माप 182 मीटर (497 फीट) है। 182 मीटर की ऊंचाई को विशेष रूप से गुजरात विधान सभा में सीटों की संख्या से मेल खाने के लिए चुना गया था।

विशेषताएं :

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर (597 फीट) ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह पिछले रिकॉर्ड धारक, चीन के हेनान प्रांत में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 54 मीटर (177 फीट) ऊंचा है। भारत में पिछली सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास परीताला अंजनेय मंदिर में भगवान हनुमान की 41 मीटर (135 फीट) ऊंची प्रतिमा थी। प्रतिमा को 7 किमी (4.3 मील) के दायरे में देखा जा सकता है।

स्मारक का निर्माण साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर किया गया है, जो नर्मदा बांध से 3.2 किमी (2.0 मील) दूर है और नीचे की ओर है। मूर्ति और उसके आसपास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से अधिक का कब्जा है, और नर्मदा नदी पर गरुड़ेश्वर वियर द्वारा बनाई गई 12 किमी (7.4 मील) लंबी कृत्रिम झील से घिरा हुआ है।

प्रतिमा को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से केवल तीन ही जनता के लिए सुलभ हैं। इसके आधार से पटेल के पिंडली के स्तर तक पहला क्षेत्र है जिसमें तीन स्तर हैं और इसमें प्रदर्शनी क्षेत्र, मेजेनाइन और छत शामिल हैं। पहले क्षेत्र में एक स्मारक उद्यान और एक संग्रहालय भी है। दूसरा क्षेत्र पटेल की जांघों तक पहुंचता है, जबकि तीसरा 143 मीटर की ऊंचाई पर देखने वाली गैलरी तक फैला हुआ है। चौथा क्षेत्र रखरखाव क्षेत्र है जबकि अंतिम क्षेत्र में मूर्ति के सिर और कंधे शामिल हैं।

पहले क्षेत्र में **संग्रहालय** सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को सूचीबद्ध करता है। साथ में एक ऑडियो-विजुअल गैलरी पटेल पर 14 मिनट की लंबी प्रस्तुति प्रदान करती है और राज्य की आदिवासी संस्कृति का भी वर्णन करती है। मूर्ति के पैर बनाने वाले कंक्रीट टावरों में प्रत्येक में दो लिफ्ट होते हैं। प्रत्येक लिफ्ट केवल 30 सेकंड में एक बार में 26 लोगों को व्यूइंग गैलरी तक ले जा सकती है। गैलरी 143 मीटर (402 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 200 लोग बैठ सकते हैं।

उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत श्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के जन्म की 138वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2013 को प्रतिमा की आधारशिला रखी थी।

स्मारक का निर्माण अक्टूबर 2018 के मध्य में पूरा हुआ; और उद्घाटन समारोह 31 अक्टूबर 2018 (वल्लभभाई पटेल की 143 वीं जयंती) को आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रतिमा को भारतीय इंजीनियरिंग कौशल के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया है।

नवंबर 2019 के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दैनिक औसत पर्यटक फुटफॉल 14,036 तक पहुंच गया, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (जो औसतन लगभग 10,000 दैनिक आगंतुकों को आकर्षित करता है) को पीछे छोड़ देता है। इसे शंघाई सहयोग संगठन के '8' में शामिल किया गया है

एससीओ की अजूबे की सूची। अपने संचालन के पहले वर्ष में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 29 लाख (2,900,000) आगंतुकों को आकर्षित किया और टिकट राजस्व में 82 करोड़ रुपये एकत्र किए।^[49] 15 मार्च 2021 तक, 50 लाख (5 मिलियन) पर्यटकों ने दौरा किया

नर्मदा टेंट सिटी :

केवड़िया में नर्मदा टेंट सिटी पर्यटकों के लिए साइट पर बुनियादी ढांचे के साथ आसानी सुनिश्चित करने का सबसे तेज़ तरीका है। टेंट सिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2018 को किया गया था और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक बगल में स्थित होने के कारण मंत्रमुग्ध कर देने वाला और शानदार दृश्य प्रदान करता है। यह न केवल रहने के लिए जगह प्रदान करता है, बल्कि यह वाटर स्पोर्ट्स, साहसिक गतिविधियों और इकोटूरिज्म की भी पेशकश करेगा।



शानदार नेचर रिट्रीट:

सरदार सरोवर बांध और आसपास के प्राकृतिक वातावरण की सुरम्य पृष्ठभूमि के बीच टेंट सिटी नर्मदा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की छाया के नीचे खूबसूरती से रखा गया है। लक्ज़रियस नेचर रिजॉर्ट शहरी यात्रियों के लिए प्रकृति के नज़दीक के अनुभव के लिए एक आदर्श स्थान है, जो तेज़-तर्रार शहरी जीवन से दूर, लुढ़कती पहाड़ियों, झीलों, जंगली क्षेत्रों और प्रदूषण मुक्त हवा के बीच में है।

टेंट सिटी नर्मदा में टेंट नेस्लिंग शानदार और अच्छी तरह से नियुक्त हैं, जहाँ पाँच सितारा भोजन पाँच सितारा आवास का पूरक है। पैकेज का एक विकल्प है, शहर से जल्दी 1-दिन के पलायन से लेकर आलसी 2-दिवसीय पलायन तक। सप्ताहांत के लिए, छुट्टियों, अवसरों, शैक्षिक यात्राओं, या कॉर्पोरेट आउटिंग के लिए, टेंट सिटी नर्मदा एक आदर्श प्रकृति वापसी है।

रिज़ॉर्ट में सभी प्रकार के पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवास के तीन आकर्षक विकल्प हैं - लक्ज़री टेंट, डीलक्स टेंट और मानक टेंट, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

फूलों की घाटी :

फूलों की घाटी (भारत वन के रूप में भी जानी जाती है), 24 एकड़ भूमि में फैली हुई है और नर्मदा नदी के किनारे रंगीन फूलों के पौधों के लिए एक आश्रय स्थल है।

फूलों की घाटी 2016 में 48,000 पौधों के साथ शुरू हुई और अब 22,00,000 पौधों तक पहुंच गई है। पाकों के अलावा, कई फोटो बूथ और सेल्फी पॉइंट विकसित किए गए हैं ताकि यात्रा की यादगार यादें ताजा की जा सकें। यह स्थान पृथ्वी पर स्थापित फूलों के इंद्रधनुष जैसा दिखता है।



इस उद्यान में 300 से अधिक प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। सजावटी फूलों, पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों, पर्वतारोहियों और लताओं का एक सही मिश्रण पत्ते के विभिन्न रंगों के साथ लगाया जाता है, जो इस क्षेत्र में हरा आवरण बनाता है। इन प्रजातियों का समामेलन इस छोटे से क्षेत्र को करामाती, तेजतर्रार और दिलचस्प बनाता है। सुरम्य स्थल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मनोरम दृश्य निश्चित रूप से आगंतुकों को हमेशा आकर्षित करता है। यह जीवंत परिदृश्य हर सर्दियों में एक करिश्माई फूल शो के लिए भी एक साइट है।

अध्याय : 5

औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध बुनियादी ढाँचा।

जिले के तीव्र आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढाँचा सुविधाएं उपलब्ध कराना एक पूर्वापेक्षा है। ऐसी सुविधाएं व्यापक परिवहन अवसंरचना, बेहतर संचार नेटवर्क, अच्छी पोस्ट और टेलीग्राफ सेवाएं, व्यापक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आदि हैं। इसके अलावा, भारी मात्रा में कच्चे माल की आसान और लागत प्रभावी उपलब्धता, तकनीकी रूप से मजबूत और कुशल उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त करने के लिए तैयार माल और सेवाओं की बिक्री के लिए मानव शक्ति भारी वितरण प्रणाली, भारी मशीनरी, निरंतर बिजली शक्ति और ईंधन व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक हैं।

बुनियादी सुविधाओं का भौतिक आयाम:

(1) विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता :

उद्यमियों को भूमि के खाली प्लॉट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आसानी से उपलब्ध हो। जिले में कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। जिले में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

(2) गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी):

नडोद तालुका का राजपिपला नर्मदा जिले में जीआईडीसी सम्पदा वाला मुख्य औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा, सागबारा, देडियापाड़ा और तिलकवाड़ा तालुका में जीआईडीसी ने औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। जीआईडीसी नए और साथ ही मौजूदा उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों की खरीद और विभिन्न बैंकों और संस्थानों से अन्य ढांचागत और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार, जिले में संतुलित औद्योगिक विकास के विकास में जीआईडीसी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न तालुका में स्थित औद्योगिक सम्पदाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम	का नाम तालुका	का नाम औद्योगिक क्षेत्र	कुल योग अर्जित क्षेत्र (आरए)	शेडों की संख्या	सं. शेड आबंटित	खाली शेड
1	नांदोस	राजपिपला	04	8	8	-
2	सागबारा	सागबारा	23	0	0	-

3	ददियापदा	ददियापदा	47	12	12	-
4	तिलकवाड़ा	तिलकवाड़ा	02	0	0	-
4	गरुड़ेश्वर	गरुड़ेश्वर	10	0	0	-
		कुल योग :	96	20	20	-

3. औद्योगिक इकाइयों के लिए जल सुविधा:

जिले में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति तीन मुख्य स्रोतों जैसे गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, सिंचाई नहर और सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त की जा सकती है।

सरदार सरोवर परियोजना:

इस परियोजना में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। 3.64 किमी में फैले विभिन्न तालुकाओं में बिछाई गई शाखा नहरों के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। वाडिया, शाखा नहर नन्दोद से शुरू होकर कोलियरी में अंत बिंदु नर्मदा जिले को पानी की आपूर्ति करती है।

(3) शक्ति:

बिजली की सुविधा :

केवड़िया में 1440 मेगा वाट क्षमता की नर्मदा जलविद्युत परियोजना वर्तमान में कार्य कर रही है। जिसके तहत नदी तल पर 1200 मेगावाट की इकाई फरवरी, 2004 में रुपये की लागत से स्थापित की गई थी। 214.08 करोड़। और, 240 मेगा वाट की क्षमता वाली एक और इकाई की स्थापना दिसंबर 2004 में केवड़िया के कनाल हेड में भी जिले में कार्यरत थी।

वड़ोदरा जिले के जम्बूवा से जुड़े तिलकवाड़ा में 132 केवी का सबस्टेशन मौजूद है।

विभिन्न तालुका में स्थित बिजली स्टेशनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सब स्टेशन का नाम	तालुका	सबस्टेशन के प्रकार	एमवीए में क्षमता
1	132 केवी तिलकवाड़ा	तिलकवादः	132/ 66	10
2	66 केवी गौडेश्वर	तिलकवाड़ा और नांदोस	66/11	10
3	66 केवी राजपीपला	नांदोस	66/11	30
4	66 केवी भाचरवदा	नांदोस	66/11	20
5	66 केवी प्रतापनगर	नांदोस	66/11	20
6	66 केवी राजपार्डी	ज़गडिया	66/11	20
7	66 केवी भालोद	ज़गडिया	66/11	10
8	66 केवी पनेठा	ज़गडिया	66/11	20

9	66 केवी ददियापदा	दीदीपदा	66/11	10
10	66 केवी चिकदा	दीदीपदा	66/11	04
11	66 केवी सागबरा	सागबरा	66/11	10
12	66 केवी अमला	नांदोस	66/11	14
13	66 केवी अनीजार	नांदोस	66/11	30
14	66 केवी राजूवाड़िया	नांदोस	66/11	30

सरदार सरोवर बांध के मुख्य बिजली संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए छह 200 मेगावाट के फ्रांसिस पंप-टरबाइन हैं और इसमें एक पंप-भंडारण क्षमता शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुख्य नहर के लिए सेवन पर एक बिजली संयंत्र में पांच 40 मेगावाट कापलान टर्बाइन-जनरेटर शामिल हैं। बिजली सुविधाओं की कुल स्थापित क्षमता 1,440 मेगावाट है।

जिले में बिजली की खपत इस प्रकार है: (2019-20)

क्रम सं.	खपत का प्रकार	बिजली की खपत (' इकाइयों में)
1	घरेलू	446.17
2	व्यावसायिक	3.03
3	औद्योगिक	240.96
4	पब्लिक स्ट्रीट लाइट	10.00
5	कृषि सिंचाई	628.10
6	पानी की टंकी	131.72
7	अन्य	13.86
	कुल योग	1473.49

सौर ऊर्जा उत्पादन:

2011 में, गुजरात सरकार ने नहर के ऊपर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना की घोषणा की, जिससे आसपास के गांवों को बिजली मिल सके और पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद मिल सके। पहले चरण में 24 मेगावाट तक की क्षमता वाली नहर की 24 किमी लंबाई के साथ पैनल लगाना शामिल है।

गैस :

जिले में कलोल से वडोदरा होते हुए अहमदाबाद होते हुए करीब 41.91 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का एक खंड है। गैस ग्रिड की प्रस्तावित लंबाई 15 किमी है जो तारापुर ब्लॉक को कवर करने की उम्मीद है।

(4) रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर:

जिले में 4 रेलवे स्टेशन हैं। आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है जो पड़ोसी जिले को वडोदरा और भरूच से जोड़ रहा है, यह निश्चित रूप से जिले में मौजूदा लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देगा। यह चार स्टेशनों अंकलेश्वर, झगड़िया, राजपीपला और वडोदरा को जोड़ेगा।

(5) सड़क अवसंरचना:

नर्मदा जिला राज्य के प्रमुख उद्योग केंद्रों के साथ सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह अहमदाबाद (194 किमी), सूरत (83 किमी) और वडोदरा (80 किमी), गांधीनगर (223 किमी), जामनगर (467 किमी), वापी (140 किमी), भावनगर (347 किमी) जैसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और एक अंकलेश्वर (74 किमी)। यह भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली (964 किमी), मुंबई (419 किमी), हैदराबाद (936 किमी), कोलकाता (1779 किमी) और चेन्नई (1493 किमी) से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

सड़क का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	सड़क का विवरण	लंबाई (किमी में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	93.60
2.	राज्य राजमार्ग	286.60
3.	जिला मुख्य सड़क	144.90
4.	जिले की अन्य सड़कें	23 4.64
4.	ग्रामीण सड़कें	1308.30
6.	नगर पालिका पक्का रोड	33 .00
	कुल	2111.04

स्रोत: सड़क एवं भवन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जिला पंचायत।

(6) सार्वजनिक परिवहन:

राज्य सरकार परिवहन निगम पूरे जिले में बसों का संचालन करता है। इसके अलावा, जिले में इन सड़कों पर जीप, रिक्शा, टैक्सी ट्रॉली, कार, ट्रक और मोटर साइकिल जैसे निजी वाहन दौड़ते हैं। जिले के आरटीओ में करीब 464748 वाहन पंजीकृत हैं। मोटर साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, टैक्सी, ट्रॉली, रिक्शा आदि से अधिक वाहनों का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। औद्योगीकरण और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एसआईआर, एसईजेड, समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि के बीच मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित की जानी चाहिए। बंदरगाह क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा सकते हैं ताकि कार्गो हैंडलिंग और वितरण की आवश्यकताओं को अधिक कुशल तरीके से प्रबंधित किया जा सके।

31 मार्च, 2020 तक आरटीओ में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या:

01-01-2001 से 31-03-2020 तक कुल पंजीकृत वाहन		
क्रमांक	वाहन वर्ग	पंजीकृत वाहन की संख्या
1	अनुकूलित वाहन	14
2	कृषि ट्रैक्टर	3991
3	रोगी वाहन	49
4	सहायक ट्रैलर	2
5	बस	117
6	टूरिस्ट वैन / ट्रैलर	2
7	निर्माण उपकरण वाहन	122
8	क्रेन घुड़सवार वाहन	8
9	अर्थ मूविंग इक्विपमेंट	3

10	शैक्षणिक संस्थान बस	1
11	ई-रिक्शा	2
12	खुदाई (वाणिज्यिक)	13
13	खुदाई (एनटी)	2
14	अग्निशमन वाहन	2

(7) एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:

जिले में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा वडोदरा और सूरत में स्थित है। साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक **सीप्लेन** सेवा 31 अक्टूबर, 2020 से शुरू हो गई है। 19-सीटर सीप्लेन में 12 यात्री बैठ सकेंगे अहमदाबाद और केवड़िया के बीच हवाई दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। सीप्लेन को दूरी तय करने में करीब 44 मिनट का समय लग रहा है।

(8) दूरसंचार सुविधा:

दूरसंचार सुविधा किसी भी जिले के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आधुनिक सुसज्जित बुनियादी ढांचे के रूप में अधिक महत्व रखती है।

जिले में तालुका वार उपलब्ध बुनियादी ढांचा इस प्रकार है::

क्रम सं	तालुका	एन अमी ऑफ़ अदला बदली	कुल योग क्षमता	काम कर रहे संबंध	प्रतीक्षा करना सूची	प्रतिशत ओ एफ यू टिलाइजेशन %
1	ददियापदा	नवी बेदवान	248	102	0	41.13
2		थपथपाना	248	64	0	24.81
3		सागबारा	496	223	0	44.96
4		ददियापदा	1400	433	0	38.07
5		सेलम्बा	744	481	0	64.64
6	राजपिपला	भूचार्डो	248	102	0	41.13
7		गरुडेश्वर	248	136	0	44.84
8		जितनगर	248	40	0	20.16
9		मंगरोल	248	107	0	43.14
10		पटना	248	84	0	33.87
11		पोइचा	248	44	0	21.77
12		वाघराली	248	64	0	24.81
13		वीरपोर	248	71	0	28.63
14		अमलेथा	488	248	0	42.87

14		गोपालपुरा	488	240	0	41.23
16		के-कॉलोनी	2000	311	0	14.44
17		लछरासी	488	321	0	64.78
18		निकोलिक	360	222	0	61.67
19		प्रतापनगर	744	333	0	44.76
20		सिसोदरा (राजस्थान)	488	347	0	71.11
		राजपिपला	4000	2414	0	48.30
		कुल योग	15176	6428	0	43.02

भारत संचार निगम लिमिटेड, जीएमटीडी, राजपिपला।

(9) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

(1) उद्योगों में स्वच्छ ईंधन की ओर धीरे-धीरे बदलाव:

गुजरात राज्य में राज्य भर में बहुत अच्छी गैस सूख गई है जिसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस में पाइप की आपूर्ति की जा रही है। कई इकाइयां जीवाश्म ईंधन (एचएसडी, कोयला आदि) से प्राकृतिक गैस में बदल गई हैं जो एक स्वच्छ ईंधन है। इसके अलावा, पीएनजी फ़ोर्साइल ईंधन की तुलना में सस्ता है। उद्योगों द्वारा स्वच्छ ईंधन की ओर धीरे-धीरे बदलाव के लिए कम लागत अतिरिक्त कारक है।

(2) लघु उद्योगों में ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना:

सरकार गुजरात सरकार ने "गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर" नामक एक विशेष संगठन की स्थापना की है। यह संस्थान कचरा प्रबंधन के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट साइट की स्थापना कर रहा है। ईटीपी और ठोस अपशिष्ट स्थल पहले से ही गुजरात राज्य में मुख्य रूप से उद्योग संघ द्वारा स्थापित और संचालित हैं।

(3) पर्यावरण मानकों का प्रवर्तन:

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानक को लागू कर रहा है और लाल और नारंगी को छोड़कर सभी गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को उत्पादन फिर से शुरू करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करनी होगी।

इसके अलावा, सरकार, गुजरात सरकार एमएसएमई इकाइयों द्वारा जल ऑडिट को प्रोत्साहित कर रही है ताकि सब्सिडी, ऑडिट शुल्क के माध्यम से पानी के उपयोग को कम किया जा सके।

सामाजिक बुनियादी सुविधाएं:

1. उद्यमिता :

जिले के पांच तालुकों में, वर्तमान में 590 से अधिक एमएसएमई संचालित हैं। सूक्ष्म पैमाने के उद्योग मुख्य रूप से मरम्मत और सेवाओं, चीनी मिट्टी की चीजें, लकड़ी के उत्पाद, कागज और रबर उत्पाद आदि में लगे हुए हैं। अधिकतम 398 इकाइयाँ जिनका निवेश रु 103.35 लाख और 459 व्यक्तियों को रोजगार पैदा करना केवल नन्दोद तालुका में केंद्रित है। जिले में आरक्षित वन क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं है।

जिले में मांग आधारित और कृषि आधारित उद्योग ज्यादातर गैर-कृषि गतिविधियों में विकसित किए गए हैं।

हालांकि सरकारी नियमों और प्रक्रिया के लिए जोखिम कारक से बचने की अवधारणा प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इसके परिणामस्वरूप कमजोर औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्पादकता विकास केंद्र, लघु उद्यम विकास संस्थान- अहमदाबाद, जिला उद्योग केंद्र- राजपीपला और अन्य गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध श्रम बल की उत्पादकता को बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए।

2. विपणन क्षमता :

कृषि उत्पादों के वितरण के लिए नर्मदा जिले में अच्छी तरह से विकसित मार्केट यार्ड हैं। किसान इन बाजारों में और खुले बाजार में भी अपनी उपज को बेचकर अपनी उपज के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य अर्जित कर सकते हैं। निर्मित और उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए जिले में अच्छा बुनियादी ढांचा है। जिले में कई संगठित और असंगठित विपणन व्यवस्थाएं स्थापित हैं।

3. क्रेडिट बैंक और उधार देने वाली एजेंसियां :

टिकाऊ और समान कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने कॉर्पोरेट मिशन के अनुरूप नाबार्ड और अग्रणी बैंक-देना बैंक ने संभावित लिंकड क्रेडिट योजनाओं की अवधारणा पेश की है। वर्ष 2020-21 के लिए संभावित लिंकड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) जिले के संबंधित विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और प्रगतिशील किसानों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

पीएलपी 2020-21 मानव और प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती कारकों, बुनियादी ढांचे और समर्थन को ध्यान में रखते हुए जिले के समग्र विकास के लिए ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के संबंध में शोषण के लिए उपलब्ध क्षमता का आकलन करने के बाद बैंक ऋण के माध्यम से जमीनी स्तर के निवेश के लिए संभावनाओं का अनुमान प्रस्तुत करता है। सेवाएं उपलब्ध हैं और सृजित होने की संभावना है। वर्ष 2020-21 के लिए संभावित लिंकड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) नर्मदा जिले का कुल ऋण रु 48,718.16 लाख है।

शैक्षिक और तकनीकी कौशल बुनियादी ढांचा:

शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	संस्थानों का प्रकार	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	731

2	माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय	130
3	फार्मसी कॉलेज	01
4	साइंस कॉलेज	01
5	कॉमर्स कॉलेज	01
6	अन्य कॉलेज	04

नर्मदा जिले के रोजगार कार्यालय में 31/03/2020 को पंजीकृत शिक्षित और बेरोजगार युवाओं की संख्या इस प्रकार हैं:

क्रम.	पारित मानक	पुरुष	महिला	कुल
1	एसएससी	8600	1018	9618
2	एचएससी	6984	2833	9817
3	बी.विज्ञान	216	76	292
4	बी.कॉम	234	113	348
5	बी 0 ए	1369	943	2312
6	होना	0	0	0
7	डिप्लोमा धारक	264	43	308
8	कारीगर (टेक), आईटीआई आदि।	1428	131	1449
9	अन्य	7847	2688	10434
	कुल योग	26944	7844	34789

स्रोत: रोजगार कार्यालय, राजपीपला ।

विकास केंद्र:

विकास केंद्र जो जिले में औद्योगीकरण को स्थापित करने और तेज करने के लिए प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक एजेंसियों की सहायता करते हैं, वे निम्नानुसार हैं:

(1) एमएसएमई-विकास संस्थान-अहमदाबाद:

एमएसएमई-विकास संस्थान, जिसे पहले एसआईएसआई के नाम से जाना जाता था, गुजरात राज्य में विकास आयुक्त, (एमएसएमई), नई दिल्ली के कार्यालय का ही एक अंग है। डीसीएमएसएमई का कार्यालय, जिसे एमएसएमई-डीओ के नाम से जाना जाता है, एक शीर्ष निकाय है और देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार और विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, समन्वय करने, निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है। एमएसएमई-डीआई, अहमदाबाद, अहमदाबाद में मुख्य संस्थान और राजकोट और सिलवासा में स्थित दो शाखा संस्थानों के माध्यम से गुजरात राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र को विस्तार सेवाएँ प्रदान करता है।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 :

भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2006 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा , लघु उद्योग मंत्रालय और एआरआई मंत्रालय का एक साथ विलय कर दिया गया और एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया गया।

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा:

- क्रेडिट
- क्लस्टर आधारित विकास
- प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन - उन्नयन समर्थन
- विपणन सहायता
- उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तिकरण
- संघों की क्षमता को सुदृढ़ करना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता - कमजोर वर्ग (एससी, एसटी, पीएच, महिला, अल्पसंख्यक और उत्तर पूर्वी क्षेत्र)

मेरा एमएसएमई मोबाइल ऐप :

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा **www** पर My MSME मोबाइल एप्लिकेशन लिंक लॉन्च किया गया । भारत में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (**MSME**) और अन्य हितधारकों के लिए **dcmsme.gov.in** । यह एप्लिकेशन एमएसएमई की नीतियों, उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के पंजीकरण, योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने (क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, विपणन, बुनियादी ढांचा, कौशल या नीति संबंधी) से संबंधित सभी सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, एमएसएमई योजनाओं के लिए आवेदन करें। लाभ, शिकायत निवारण, एमएसएमई योजना दिशानिर्देश और परियोजना प्रोफाइल, एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्यालयों और संगठनों के लिए वेब लिंक, एमएसएमई फेसबुक पेज और एमएसएमई ट्विटर पेज आदि।

#उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र:

अधिसूचना के अनुसार डी.टी.डी. उद्यम पंजीकरण के 26/06/2020, ईएम- पार्ट- II या यूएएम के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा उद्यम उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर से पंजीकृत होंगे : www.udyamregistration.gov.in जुलाई 2020 के पहले दिन या उसके बाद।

संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण इस प्रकार है:

समग्र मानदंड: निवेश और वार्षिक कारोबार			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण और सेवाएं	निवेश रुपये नहीं है। 1 करोड़ और टर्नओवर 4 करोड़ रुपये नहीं है।	निवेश रुपये नहीं है । 10 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ रुपये नहीं है ।	निवेश रुपये नहीं है। 40 करोड़ और टर्नओवर 240 करोड़ रुपये नहीं है ।

सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम बनना।—

- (1) कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह स्व-घोषणा के आधार पर दस्तावेज़, कागजात, प्रमाण पत्र या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता के बिना, उद्यम पंजीकरण पोर्टल में ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण दर्ज कर सकता है।
- (2) पंजीकरण पर, "उद्यम पंजीकरण संख्या" के रूप में एक उद्यम (उद्यम में 'उद्यम' के रूप में संदर्भित) पंजीकरण पोर्टल को ज्ञात होने के लिए एक स्थायी पहचान संख्या सौंपी जाएगी
- (3) पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर एक ई-प्रमाण पत्र, अर्थात् "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया :

- (1) पंजीकरण के लिए फॉर्म उद्यम पंजीकरण पोर्टल में दिए गए अनुसार होगा।
- (2) उद्यम पंजीकरण दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।
- (3) उद्यम पंजीकरण के लिए आधार संख्या की आवश्यकता होगी।
- (4) आधार संख्या एक प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में प्रोपराइटर की, पार्टनरशिप फर्म के मामले में मैनेजिंग पार्टनर की और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता की होगी।
- (5) कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या सहकारी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार संख्या के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन प्रदान करेंगे।
- (6) यदि कोई उद्यम पैन के साथ एक उद्यम के रूप में विधिवत पंजीकृत है, तो पिछले वर्षों की जानकारी में किसी भी तरह की कमी, जब उसके पास पैन नहीं था, स्व-घोषणा के आधार पर भरा जाएगा।
- (7) कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दाखिल नहीं करेगा: बशर्ते कि विनिर्माण या सेवा या दोनों सहित कई गतिविधियों को एक उद्यम पंजीकरण में निर्दिष्ट या जोड़ा जा सकता है।
- (8) जो कोई जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उद्यम पंजीकरण या अपडेशन प्रक्रिया में प्रकट होने वाले स्वयं घोषित तथ्यों और आंकड़ों को दबाने का प्रयास करता है, वह अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

उद्यमों की सुविधा और शिकायत निवारण :

- (1) विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई) सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में कार्यरत चैंपियंस नियंत्रण कक्ष पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सूक्ष्म, लघु और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेंगे। और मध्यम उद्यम हर संभव तरीके से।
- (2) जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) अपने जिलों में एकल खिड़की सुविधा प्रणाली के रूप में भी कार्य करेंगे।
- (3) कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या की कमी सहित किसी भी कारण से उद्यम पंजीकरण दाखिल करने में सक्षम नहीं है, वह अपनी आधार नामांकन पहचान पर्ची या आधार नामांकन अनुरोध की प्रति के साथ उद्यम पंजीकरण उद्देश्यों के लिए उपरोक्त किसी भी एकल खिड़की प्रणाली से संपर्क कर सकता है या बैंक फोटो पास बुक या मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और सिंगल विंडो सिस्टम आधार संख्या

प्राप्त करने और उसके बाद उद्यम पंजीकरण की आगे की प्रक्रिया सहित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे।

(4) किसी भी विसंगति या शिकायत के मामले में, संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक उद्यम द्वारा प्रस्तुत उद्यम पंजीकरण के विवरण के सत्यापन के लिए जांच करेंगे और उसके बाद मामले को आवश्यक टिप्पणियों के साथ निदेशक या को अग्रेषित करेंगे। या भारत के, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित आयुक्त या उद्योग सचिव, जो उद्यम को नोटिस जारी करने के बाद और अपना मामला पेश करने का अवसर देने के बाद और निष्कर्षों के आधार पर, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम मंत्रालय, सरकार को विवरण में संशोधन या सिफारिश कर सकते हैं।

चैंपियन पोर्टल :

उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग।

आपको **बड़ा** बनाने के लिए हमारे छोटे हाथ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसएमई सशक्त बनाने के लिए 1 जून, 2020 को शुरू की चैंपियन:प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म

एमएसएमई के लिए एकल खिड़की प्रणाली देश

देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मदद और बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत, सशक्त, मजबूत, संगठित और प्रौद्योगिकी संचालित मंच को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक महसूस किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग होगा। तदनुसार, सिस्टम का नाम चैंपियंस है। यह मूल रूप से छोटी इकाइयों को मदद और हाथ पकड़कर बड़ी बनाने विशेष रूप से, उनकी समस्याओं और शिकायतों को हल करके के लिए है।

चैंपियंस के तीन मूल उद्देश्य :

- 1) इस कठिन परिस्थिति में एमएसएमई को वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि के मामले में मदद करना।
- 2) एमएसएमई को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करना।
- 3) चिंगारी की पहचान करने के लिए, यानी, उज्ज्वल एमएसएमई जो वर्तमान में सामना कर सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं।

कोई भी उद्यम वेब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है:

WWW.CHAMPIONS.GOV.IN (ई-मेल आईडी: Champions@gov.in)

एमएसएमई की सभी योजनाओं का विवरण वेबसाइट dcmsme.gov.in/ <https://msme.gov.in> पर उपलब्ध है।

गुजरात सरकार, उद्योग और खान विभाग ने गुजरात में MSMEs की प्रतिस्पर्धा, विकास और समग्र विकास में सहायता और बढ़ाने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति 2020 को अधिसूचित किया है।

उद्योग आयुक्तालय गुजरात सरकार के उद्योग और खान विभाग की कार्यकारी शाखा है। कार्यालय को राज्य और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उद्योग आयुक्तालय निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण की सुविधा और औद्योगिक सुधार लाकर राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह विनिर्माण और सेवा उद्यमों के विकास और उन्नयन के लिए उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, कार्यालय उद्योगों को विभिन्न लाभ और पैकेज प्रदान करता है।

यह पॉलिसी 7 अगस्त 2020 से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी।

दृष्टि :

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास द्वारा संचालित अगली पीढ़ी के टिकाऊ विनिर्माण और सेवा उद्योग के लिए गुजरात को एक वैश्विक व्यापार गंतव्य बनाने के लिए और इस तरह "आत्मनिर्भर भारत" में महत्वपूर्ण योगदान देना।

मिशन :

समर्थित राज्य में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए:

- समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा
- प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन
- व्यापार करने में आसानी
- आत्मनिर्भर भारत के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना
- रोजगार सृजन: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता : वोकल फॉर लोकल टू बी ग्लोबल
- प्रभावी नीति कार्यान्वयन

उद्देश्य:

- एकल खिड़की द्वारा सुगम कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए प्रणाली
- उद्योगों को उच्च गुणवत्ता मानक स्थापित करने और निर्यात बढ़ाने में सक्षम बनाना
- औद्योगिक रूप से अविकसित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण रखना और सुविधा प्रदान करना समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास
- टिकाऊ, स्वच्छ विनिर्माण को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना और अभिनव उद्योग 4.0 अभ्यास

- एमएसएमई को मजबूत करने और क्लस्टर विकास की सुविधा के लिए
- उत्पाद खंड में कुल योग मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए: एक " आत्मानिभर भारत" का उद्देश्य
- अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए
- कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना रोजगार, निर्यात, निवेश आदि की संभावना।
- राज्य में सेवा क्षेत्र के उद्योगों के विकास को सुगम बनाने के लिए
- अत्याधुनिक, टिकाऊ औद्योगिक अवसंरचना की सुविधा के लिए
- राज्य में उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए

गुजरात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम, 2019:

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करना है। गुजरात में एक एमएसएमई अब 'इरादे की घोषणा' जमा करके राज्य नोडल एजेंसी से एक पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर संचालन शुरू कर सकता है। एमएसएमई क्षेत्र को अब पहले तीन वर्षों के लिए विभिन्न अनुमोदन लेने से छूट दी गई है। यह पहल एमएसएमई की स्थापना की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी और इससे राज्य के भीतर रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

नई औद्योगिक नीति 2020 और अन्य प्रोत्साहनों की सभी योजनाओं का विवरण वेब साइट <https://ic.gujarat.gov.in> पर उपलब्ध है

अध्याय : 6

वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य :

(1) सामान्य औद्योगिक जलवायु :

आमतौर पर जिले के एमएसएमई डायमेंशनल और मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के बहुसंख्यक होने के कारण कुशल और सुशिक्षित लोगों की कमी के कारण जिले का औद्योगिक परिदृश्य बहुत दुखद है। आरक्षित वन क्षेत्र में वन नीति के अनुसार जिले में उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, जिले के बाहर के उद्यमी जिले में लघु और मध्यम स्तर पर उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। इन सभी कारकों ने जिले में औद्योगिक विकास को धीमा कर दिया है।

इसलिए, धारणा और प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त देखभाल और समर्थन आवश्यक है और गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से लंबे समय तक जीवित रहने के लिए एमएसई को क्रमिक और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना आवश्यक है।

जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। केला और कपास का उत्पादन जिले की प्रमुख बागवानी फसलें हैं। मरम्मत और सेवाओं, लकड़ी उत्पादों, कागज और खाद्य उत्पादों में लगे 860 सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसएमई अधिनियम में अपंजीकृत सहित) जिले में मौजूद हैं, जिनमें से 300 से अधिक इकाइयां नंदोद तालुका में हैं।

उद्योग आधार ज्ञापन में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या (30.06.2020 तक)

(विनिर्माण और सेवा क्षेत्र) सहित उद्यम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
सूक्ष्म	497
लघु	82
मध्यम	11
कुल	490

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या (22.06.2021)

(विनिर्माण और सेवा क्षेत्र) सहित उद्यम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
सूक्ष्म	272

लघु	10
मध्यम	0
कुल	282

नर्मदा जिले के पांच तालुकों में, 490 से अधिक सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम संचालित हैं और 990 नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सूक्ष्म उद्यम मुख्य रूप से मरम्मत और सेवाओं में लगे हुए हैं और लघु उद्योग सिरेमिक, लकड़ी उत्पाद, और कागज और रबड़ उत्पाद आदि में लगे हुए हैं। नंदोद तालुका में अधिकतम 398 इकाइयां हैं जिनमें रुपये का निवेश है। 103.34 लाख और 449 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले केंद्रित हैं।

राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं पर जागरूकता की कमी के कारण जिले का औद्योगिक परिदृश्य संतोषजनक नहीं है।

• विकास के लिए पहचाने गए उपयुक्त/उपयुक्त क्लस्टर :-

एमएसई-सीडीपी के तहत केला वेफर्स निर्माण इकाइयों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र

केले के रेशे का निष्कर्षण, ब्लीचिंग और केले के रेशे उत्पाद- प्रदर्शन इकाई के बाद इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

भारत सरकार ने जनवरी, 2018 में 2022 तक एक नए भारत की दृष्टि के साथ 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' पहल शुरू की है, जहां मानव विकास सूचकांक के तहत भारत की रैंकिंग में सुधार करने, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी बुनियादी ढांचे के समग्र संकेतकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा कुल 114 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है।

उनमें से दो जिले अर्थात् नर्मदा और दाहोद गुजरात के जिले हैं।

सचिव (एमएसएमई) और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के साथ पत्राचार प्रमुख गुजरात के सचिव एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा, निदेशक, एमएसएमई-डीआई, अहमदाबाद द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है।

➤ निदेशक, एमएसएमई-डीआई, अहमदाबाद - अध्यक्ष

➤ राज्य निदेशक, केवीआईसी, अहमदाबाद - सदस्य

➤ जोनल महाप्रबंधक, एनएसआईसी, अहमदाबाद - सदस्य

- महाप्रबंधक, एमएसएमई टूल रूम, अहमदाबाद - सदस्य
- प्रबंधक, जूट बोर्ड, अहमदाबाद - सदस्य
- इंडस्ट्रीज आयुक्त गांधीनगर- सदस्य के कार्यालय के प्रतिनिधियों
- एमएसएमई-डि, संबंधित जिले के अहमदाबाद के नोडल अधिकारी।

अध्याय : 7

नए एमएसएमई/ औद्योगिक विकास की संभावनाएं :

नर्मदा जिला सबसे पिछड़े जिलों में से एक है जहां बहुसंख्यक लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। इसके अलावा, भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, औद्योगिक जिले के लिए दूरस्थ और इसकी आदिवासी अनुसूचित जाति आबादी के बीच शिक्षा और कुशल श्रम की कमी, जोखिम लेने वाली प्रकृति और उद्यमिता प्रयासों की कमी के परिणामस्वरूप जिले में औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया हुई है। हालांकि, कृषि आधारित और पशुधन आधारित और साथ ही खनिज आधारित उद्योगों में जिले में विकास की अच्छी गुंजाइश है। इसके अलावा, जिले में उत्पादन के लिए कई बाजार उन्मुख वस्तुओं को भी लिया जा सकता है।

जिले में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों और पिछले कुछ वर्षों से संचालित मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों और कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उद्योगों को पर्याप्त क्षमता वाला माना जाता है। संसाधन आधारित उद्योगों की संभावनाओं की जानकारी इस प्रकार है।

नर्मदा जिला में सामान्य निम्न संसाधन में आधारित उद्योगों संभावना है ।

(1) कृषि और खाद्य आधारित उद्योग:

क्रमांक	विवरण
1	फल डिब्बाबंदी
2	चावल फैक्ट्री
3	अचार
4	फलों के रस और स्कैश
5	पशु का चारा
6	नमकीन
7	बिस्कुट
8	पपीते से तुती फल
9	आम का रस
10	मैंगो पाउडर
11	मूंगफली भूनना
12	मसाला पाउडर
13	ममारा/पोवा
14	पॉपकॉर्न चाहिए
14	आलू वेफर
16	केला वेफर
17	केला फाइबर
18	केले के रस का पानी
19	अवशोषित सामग्री के रूप में क्रश के ऊपर केले के गार को सफेद करने वाले सैनिटरी

	नैपकिन ।
--	----------

(2) रासायनिक और संबद्ध / प्लास्टिक आधारित उद्योग:

1	पीवीसी दरवाजे और खिड़कियां
2	भंडारण पानी की टंकी
3	इंजेक्शन ढाला आइटम
4	एलडीपीई / एचडीपीई फिल्म बैग
5	पीवीसी प्रबलित सक्शन पाइप
6	पॉलीफोन बैग
7	प्लास्टिक के खेलौने
8	सर्जिकल और औद्योगिक दस्ताने
9	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सहायक उपकरण पार्ट्स
10	मछली पकड़ने का जाल
11	नायलॉन मोनोफिलामेंट यार्न
12	कठोर पॉलीथीन पाइप

(3) वन और लकड़ी आधारित उद्योग:

1	आरा मशीन
2	लकड़ी का फ़र्निचर
3	हस्तशिल्प
4	हर्बल वृक्षारोपण
5	लकड़ी के औजार
6	प्लाईवुड चेस्ट
8	मोज़ेक टाइल
9	एमरी पाउडर
10	बढ़ईगीरी
11	लकड़ी का शिल्प

(4) खनिज आधारित उद्योग:

1	भवन निर्माण ईंटें
2	मिट्टी के बर्तनों
3	सीमेंट ब्लॉक
4	फ़्लोरिंग टाइलें
5	छत की टाइलें

(5) इंजीनियरिंग और धातु आधारित उद्योग:

1	औद्योगिक घाटी
2	कमी गियर बॉक्स
3	ऑटोमोबाइल स्प्रिंग्स कोल स्प्रिंग
4	कार्यकारी और सम्मेलन अध्यक्ष
5	दबावमापक यन्त्र
6	औद्योगिक उपयोग के लिए धातुई फिल्टर
7	पिस्टन के छल्ले
8	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
9	बॉल बेयरिंग
10	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग उपकरण
11	ड्राई सेल बैटरी और स्टोरेज बैटरी

(6) लाइव स्टॉक और चमड़ा आधारित उद्योग:

1	चमड़े के जूते और चमड़े के सामान
2	अस्थि चूर्ण
3	चमड़े के सजावटी सामान
4	वस्त्र और खेल के सामान
4	चमड़े के बैग और पर्स
6	लकड़ी का काम
7	चमड़ा कमाना
8	दुग्धालय

(7) मरम्मत और सेवा उद्यम :

1	ज़ेरोक्स सेंटर
2	कंप्यूटर जॉब वर्क एंड ट्रेनिंग सेंटर
3	साइबर कैफे, नेटवर्क, ई-मेल सेवा, इंटरनेट सेवा
4	मोबाइल फोन सेवा
5	ऑटोमोबाइल पुर्जे, सेवा और मरम्मत
6	वीडियो लाइब्रेरी
7	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत

8	इस्पात फैब्रिकेशन
9	इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयरिंग
10	कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग
11	फास्ट फूड और स्नैक पार्लर
12	आइसक्रीम का दुकान
13	पैथोलॉजी प्रयोगशाला

(8) कपड़ा उद्योग:

1	होज़री
2	ग्रे कपड़ा प्रसंस्करण
3	घुमा
4	टेक्सचराइजिंग
5	यार्न की क्रिम्पिंग
6	बुनाई
7	पावर करघे
8	यार्न की क्रिम्पिंग
9	कपास बुना हुआ

(9) सहायक और अन्य विविध।

क्रमांक	विवरण
1	हार्डवेयर आइटम जैसे नट, बोल्ट, वाशर, नाखून आदि।
2	फिनाइल, टाइल्स, क्लीनर, एसिड
3	तार रस्सियों और अन्य उठाने की सामग्री
4	विभिन्न गुणों की ढलाई
4	अपवर्तक
6	चिपकने
7	गंधक
8	हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुष्क रासायनिक पाउडर
9	आग की ईंटें
10	एलपीई नली
11	तेल और तेल
12	निकालने

13	कपास का कचरा
14	साबुन का स्टॉक
14	पॉलीथीन बैग
16	टिशू पेपर्स
17	प्रिंटर केबल
18	इलेक्ट्रिकल सामग्री
19	एमएस इलेक्ट्रोड
20	पॉलीथीन बैग

अध्याय : 8

योजनाएं और हस्तक्षेप

(अ) विकास के लिए पहचाने गए उपयुक्त/उपयुक्त क्लस्टर:-

MSE-CDP के तहत केला वेफर्स निर्माण इकाइयों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र केले के रेशे का निष्कर्षण, ब्लीचिंग और केले के रेशे उत्पाद-प्रदर्शन इकाई के बाद इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

एमएसई-सीडीपी के तहत:

केवीआईसी द्वारा केला फाइबर निष्कर्षण, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण इकाई की इकाई के लिए किया गया प्रदर्शन

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेकर विपणन सहायता

मुद्रा, पीएमईजीपी आदि के तहत वित्तीय सहायता के लिए मोबिलिज़ एड मौजूदा कुशल व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए।

संगठनात्मक एड कौशल विकास कार्यक्रमों मुद्रा(एमयूडीआरए), पीएमईजीपी आदि के तहत वित्तीय सहायता जुटाने के बाद।

(ब) बड़े /मध्यम पैमाने के उद्योग:

संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों और 250 करोड़ रुपये (समग्र मानदंड) के कारोबार को बड़ी औद्योगिक इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।। एक उद्यमी या एक बड़ी परियोजना स्थापित करने की इच्छुक कंपनी को उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार (GOI) से औद्योगिक लाइसेंस के रूप में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जुलाई 1991 में, भारत सरकार ने उदारीकरण किया। कुछ उद्योगों को छोड़कर, जो सामरिक महत्व के हैं, लाइसेंस प्रक्रिया और लगभग सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंसिंग के दायरे से छूट दी गई है। निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) की स्थापना या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में एक परियोजना स्थापित करने के मामले में, संबंधित एसईजेड के विकास आयुक्त से अनुमति पत्र (एलओपी) प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार, एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया या तो आईईएम दाखिल करना, आशय पत्र (एलओआई) / औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना या 100% ईओयू या एसईजेड इकाई के मामले में अनुमति पत्र (एलओपी) प्राप्त करना होगा।

मध्यम और बड़े पैमाने और अन्य उद्योगों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	यूनिट का नाम	तालुका	उत्पादन
1	श्री नर्मदा शुगर इंडस्ट्री को ऑप. सामाजिक. लिमिटेड, धारीखेड़ा	नांदोस	चीनी

2	श्री जीएसएल (आई) प्राइवेट लिमिटेड, अमलेथा	नांदोस	धागा
3	ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, करण देव गांव में: जितनगर	नांदोस	शक्ति
4	मेसर्स अमर कार्बन एंड केमिकल्स, राजपिपला	नांदोस	सक्रिय कार्बन
5	मेसर्स प्रशांत फार्मास्युटिकल्स, राजपिपला	नांदोस	आयुर्वेदिक दवाएं
6	मेसर्स भगवतीकृपा मार्बल इंडस्ट्रीज, राजपिपला	नांदोस	मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग
7	श्रम ज्योति वुड वर्क्स, राजपिपला	नांदोस	लकड़ी का फर्निचर
8	मेसर्स महालक्ष्मी क्वारी वर्क्स, वानस्ला	नांदोस	रबर ग्रीट और कापची
9	न्यू संदीप टायर, राजपिपला	नांदोस	टायर रीमोल्टिंग
10	मेसर्स केसरी नंदन पाइप्स, राजपिपला	नांदोस	एचडीपीई पाइप्स
11	एमजे पोल फीट, राजपिपला	नांदोस	सीमेंट पाइप्स
12	मेसर्स पीआर फ्यूल, धारीखेड़ा	नांदोस	कृषि अपशिष्ट का संग्रह, प्रक्रिया और वितरण

(स) नर्मदा जिले में राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची।

- शून्य -

(द) औद्योगिक संघों और चैंबर ऑफ कॉमर्स का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	एसोसिएशन/चैंबर ऑफ कॉमर्स	टेलीफोन नं.
1	राजपिपला स्मॉल स्केल एंड ओनर्स एसोसिएशन पी.बी. नंबर 42, प्लॉट नंबर: 1/44/1, जीआईसीडी, राजपिपला (तालुका: नंदोद)	02640-220062
2.	राजपिपला विविध वेपारी मंडल, पारिख स्टेनोरी मार्ट, स्टेशन रोड, राजपिपला-393144	02640-220677-
3.	नर्मदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सी / ओ। शेठ एंड कंपनी स्टेशन रोड, राजपिपला राजपिपला-393144	02640-220197

(य) शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रमांक	संस्थानों का प्रकार	संख्या
1.	फार्मसी कॉलेज	01
2.	साइंस कॉलेज	01
3.	कॉमर्स कॉलेज	01
4.	महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज	01
4.	आईटीआई	04

(ब) औद्योगिक क्लस्टर/डिजाइन/आईपीआर/जीआई टैग जैसी चल रही योजनाएं :

एमएसई-सीडीपी केला फाइबर निष्कर्षण, ब्लीचिंग और केला फाइबर उत्पादों के तहत केला वेफर्स निर्माण इकाइयों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र- इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के बाद प्रदर्शन इकाई।

नर्मदा जिले को सरकार द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में पहचाना गया है। भारत की। एमएसई-सीडीपी के तहत क्लस्टर स्थापित करने की संभावनाओं में से एक केले की फसल पर आधारित है जिसे पर्याप्त मात्रा में उगाया जा रहा है। केले का फल लेने के बाद, केले के तने का निपटान एक समस्या है लेकिन यह इसके लिए एक बहुत अच्छा कच्चा माल है:

- 1) केले के रेशे का निष्कर्षण - विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा यार्न के साथ सम्मिश्रण के लिए किया जा सकता है और एफआरपी आदि में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 2) रेशे के निष्कर्षण के दौरान निकलने वाले तरल को एसएपी जल कहा जाता है जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है।
- 3) बचे हुए को सुखाया जा सकता है और सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए शोषक सामग्री के रूप में पाउडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

गुजरात के आकांक्षी जिले में एमएसई-सीडीपी के तहत हस्तक्षेप की स्थिति।

हस्तक्षेप प्रस्तावित	आज तक की स्थिति
केले के प्रसंस्करण के लिए क्लस्टर निर्माण	एमएसएमई-डीआई, अहमदाबाद और बागवानी विभाग के संयुक्त प्रयासों के कारण। गुजरात सरकार ने केले के रेशे निष्कर्षण की 09 इकाइयां स्थापित की हैं। अधिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। एक बार 20 इकाइयां आ जाने के बाद, फाइबर के आगे प्रसंस्करण के लिए सीएफसी के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(2) 31/03/2021 को जिले में उद्यम पंजीकरण की संख्या :

(विनिर्माण और सेवा क्षेत्र) सहित उद्यम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
सूक्ष्म	272
लघु	10
मध्यम	0
कुल	282

विकास की प्रवृत्ति:

एग्रो सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है। कृषि जिले में ग्रामीणों के लिए स्थायी आजीविका और रोजगार पैदा करने का अधिकतम अवसर प्रदान करती है।

मरम्मत और सेवाओं, लकड़ी के उत्पादों, कागज और खाद्य उत्पादों आदि में लगी कुल 590 एमएसएमई इकाइयां जिले में मौजूद हैं, जिनमें से 400 से अधिक इकाइयां नंदोद तालुका में मौजूद हैं, जैसे कपड़ा, चीनी और रसायन उद्योगों। पिछले दो दशक में प्रमुख निवेश में पर्याप्त वृद्धि देखी है।

आजकल इको एडवेंचर टूरिज्म की अवधारणा दुनिया का विकास कर रही है। गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने गुजरात राज्य के बाहर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नर्मदा जिले में 6 स्थलों का चयन किया है। चयनित स्थल शूलपनेश्वर, केवड़िया, विशालखाड़ी, माल-समोट, जरवानी, और कदिया डूंगर हैं।

नर्मदा में हर्बल बॉटनिकल गार्डन है, जिसमें हर्बल पौधों की लगभग 70 प्रजातियां शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार के लिए किया जाता है, और यह जिले में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है।

अध्याय : 9

आत्मनिर्भर भारत आंदोलन आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों के तहत

आत्मनिर्भर भारत आंदोलन:

हाल ही में, माननीय प्रधान मंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ ' आत्मनिर्भर भारत अभियान (या आत्मनिर्भर भारत मिशन)' की घोषणा की है - मिशन को प्राप्त करने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपये ।

घोषित आर्थिक पैकेज 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10% है ।

राशि में आरबीआई के उपायों और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भुगतान को शामिल करते हुए लॉकडाउन की शुरुआत में पहले से घोषित पैकेज शामिल हैं ।

पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ।

मिशन को **दो चरणों** में पूरा किया जाएगा :

चरण 1: यह चिकित्सा वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और खेलौने जैसे क्षेत्रों पर विचार करेगा जहां स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है।

चरण 2: यह रत्न और आभूषण, फार्मा और स्टील आदि जैसे उत्पादों पर विचार करेगा।

जिले में आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ :

- 1) अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि क्रांति लाती है
- 2) इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो बने भारत की पहचान
- 3) 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी-संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित प्रणाली
- 4) वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।
- 5) मांग, जिससे हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाना चाहिए ।

स्वॉट विश्लेषण:

1) ताकत: नर्मदा जिला अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ बहुत समृद्ध है। एग्रो सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है। कृषि जिले में ग्रामीणों के लिए स्थायी आजीविका और रोजगार पैदा करने का अधिकतम अवसर प्रदान करती है ।

(2) कमजोरी: चूंकि, नर्मदा जिले में बहुसंख्यक लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, कुशल व्यक्तियों की कमी है, कम साक्षरता दर, वन क्षेत्र और उद्यमी बनने के लिए पहल जोखिम की कमी वाष्पीकरण के लिए अधिक गुंजाइश नहीं होने का मुख्य कारण है। . इसलिए, गुजरात राज्य के अन्य जिलों की तुलना में जिले में औद्योगिक विकास जिले में कम है।

(3) अवसर: नर्मदा जिले में पर्यटन अब बहुत विकसित हो रहा है : सरदार सरोवर बांध , स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी और फूलों की घाटी नर्मदा जिले में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं । आस-पास के लोगों को इस आकर्षण स्थलों में बहुत अधिक रोजगार मिल रहा है।

(4) खतरे: चूंकि, नर्मदा जिले में बहुसंख्यक लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, कुशल व्यक्तियों की कमी है, कम साक्षरता दर, वन क्षेत्र और उद्यमी बनने के लिए पहल जोखिम की कमी के लिए अधिक गुंजाइश नहीं होने का मुख्य कारण है। वाष्पीकरण। इसलिए, जिले में औद्योगिक विकास गुजरात राज्य के अन्य जिलों की तुलना में जिले में कम पाया जाता है

अध्याय : 10

जिला औद्योगिक विकास योजना। विभिन्न योजनाओं के तहत:

क्रमांक	विकास गतिविधि	वित्त पोषण (रु. लाख में)			टिप्पणियां
		भारत सरकार	राज्य सरकार	दूसरों को पसंद है एसपीवी आदि	
1	पोस्ट कोविड- 19 पुनरुद्धार पैकेज : बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले पैकेज के तहत MSMEs को ऋण स्वीकृति / संवितरण । प्राप्त/ अनुमोदित आवेदनों की संख्या :4618	2466 लाख	-	-	
2	मुख्यमंत्री अमृतम योजना दावों की संख्या: 2942	-	484.62	-	
3	विकेंद्रीकृत जिले की योजना के लिए	-	987.40	-	
4	क्लस्टर विकास कार्यक्रम	अधिकतम का 80% तक । लागत रु.20 करोड़।	10%	10%	

अध्याय : 11

किससे संपर्क करें और किसलिए?

उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए अंतर एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	एजेंसियों का नाम और पता
1.	उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र	जिला उद्योग केंद्र, 2 nd मंजिल, जिला सेवा सदन, राजपीपला, जिला। नर्मदा और एमएसएमई-डीआई, अहमदाबाद।
2.	परियोजना प्रोफाइल की पहचान, तकनीकी- आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श सेवाएं, बाजार सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट।	एमएसएमई-डीआई, 4 ^{वें} तल, हरसिद्ध चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद.380014.
3.	भूमि और औद्योगिक शेड	जीआईडीसी, प्लॉट नंबर: 624 / बी, जीआईडीसी, वालिया रोड , अंकलेश्वर, जिला। भरूच
4.	वित्तीय सहायता	बैंक ऑफ बड़ौदा, (जिला लीड बैंक), कालिया भूत सर्कल, राजपीपला, जिला नर्मदा
4.	सरकार के तहत कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ।	एनएसआईसी, 202-203, समृद्धि बिल्डिंग, नं. पुराना गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद-380 014
6.	किराया/खरीद के आधार पर संयंत्र और मशीनरी	एनएसआईसी, 202-203, समृद्धि बिल्डिंग, नं. पुराना गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद-380 014
7.	बिजली / बिजली	दक्षिण गुजरात Vijnigam co.Ltd., तिलकवाड़ा, जिला। नर्मदा ।
8.	तकनीकी तरीका	एमएसएमई-टूल रूम, (इंडो-जर्मन टूल रूम), प्लॉट नंबर 4003, फेज IV, जीआईडीसी, वटवा, अहमदाबाद: 382 444
9.	गुणवत्ता मानक	बीआईएस, खानपुर, अहमदाबाद
10.	विपणन/निर्यात सहायता	एमएसएमई-डीआई, 4 ^{वें} तल, Harsiddh चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद.380 14.

11	अन्य प्रचार एजेंसियां	1) एमएसएमई आयुक्त, ब्लॉक नंबर -1 और 2, उद्योग भवन, गांधीनगर-382 017 2) उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडी) ब्लॉक नंबर 1, 9 ^{वीं} मंजिल, उद्योग भवन, सेक्टर-11 गांधीनगर 382 017 3) एमएसएमई टूल रूम / इंडो- जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर) प्लॉट नंबर 4003, फेज-IV जीआईडीसी, वटवा , अहमदाबाद
----	-----------------------	---

सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए कदम महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिए गए हैं:

- (1) उचित परियोजना का चयन
- (2) उपयुक्त प्रौद्योगिकी और मशीनरी का चयन
- (3) वित्त प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य योजना
- (4) बुनियादी ढांचे की अवधारणा: कारखाने की इमारत का निर्माण, बिजली, सीवरेज और संचार आदि जैसे आवश्यक कनेक्शन की व्यवस्था, श्रम और कार्मिक, कच्चे माल की खरीद।
- (5) जिले के संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र भरना।
 - (6) कुछ उत्पादों आदि में नियामक, कराधान, पर्यावरण मंजूरी जैसे अनुमोदन की स्वीकृति।
 - (7) गुणवत्ता प्रमाणन का पंजीकरण

अध्याय : 12

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

नर्मदा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है। जिला आरक्षित वन और समृद्ध कृषि के साथ धन्य है लेकिन ये संसाधन लगभग अप्रयुक्त हैं। कृषि उपज को आगे संसाधित नहीं किया जा रहा है जो ऐसा करने पर जिले के आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। केला एक प्रमुख फल है जिसकी खेती 10000 हेक्टेयर से अधिक में की जा रही है और केवल फल बेचा जा रहा है और केले के पौधे के शेष भाग का निर्माण करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है: केला फाइबर, जिससे कपड़ा सहित कई उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है यदि आगे प्रक्रिया, एसएपी पानी जो कई खनिजों में समृद्ध है, केले के फाइबर के निष्कर्षण के दौरान उत्पादित उत्पाद है और यह बहुत अच्छी तरह खाद है, फाइबर निष्कर्षण के बाद और केले भाप से बचा हुआ एसएपी पानी एक बहुत अच्छा शोषक है और इसका उपयोग किया जा सकता है सैनिटरी नैपकिन जैसे उत्पादों का निर्माण। यह एकमात्र फसल है जो जिले के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।

आसपास के जिले भरूच और वडोदरा औद्योगिक रूप से विकसित हैं और एमएसएमई सहित कई उद्योग या तो विस्तार या विविधीकरण की तलाश में हैं। ऐसी इकाइयों को नर्मदा जिले में औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और ऐसी इकाइयां जिले की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि यह राज्य के अन्य हिस्से के साथ रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

जिले में प्रचुर मात्रा में श्रमिक हैं जो भरूच और वडोदरा जिले में प्रवास करते हैं और वहां औद्योगिक इकाई में काम करते हैं। इन मजदूरों के पास उपलब्ध अनुभव और कौशल का उपयोग जिले में एमएसएमई के विकास के लिए भी किया जा सकता है।

सरकार की औद्योगिक नीति-2020 के तहत। गुजरात के, जिले के तालुकों में विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

जिले को उपलब्ध संसाधनों और जिले की ताकत का दोहन करने के लिए जिले में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक और रोजगार परिदृश्य के उत्थान के लिए केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

अध्याय : 13

जिले में संसाधनों की सूची

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की विस्तार सूची।

औद्योगिक संघों और चैंबर ऑफ कॉमर्स का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	एसोसिएशन/चैंबर ऑफ कॉमर्स	टेलीफोन नं.
1	राजपिपला स्मॉल स्केल एंड ओनर्स एसोसिएशन पी.बी. नंबर 42, प्लॉट नंबर: 1/44/1, जीआईसीडी, राजपिपला (तालुका: नंदोद)	02640-220062
2.	राजपिपला विविध वेपारी मंडल, पारिख स्टेडोनरी मार्ट, स्टेशन रोड, राजपिपला-393144	02640-220677-
3.	नर्मदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, सी / ओ। शेठ एंड कंपनी स्टेशन रोड, राजपिपला राजपिपला-393144	02640-220197

पीएसयू की विस्तृत सूची

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का नाम	टेलीफोन नं
1	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) रजि. कार्यालय: ब्लॉक नंबर 12, पहली मंजिल, नया सचिवालय, गांधीनगर गुजरात	ई-मेल: cio@sardarsarovardam.org फोन: 3220669 (सी), 3223418 (एमडी), फैक्स: 3223046 वेबसाइट: www.sardarsarovardam.org,

गैर सरकारी संगठनों की सूची:

क्रमांक	ट्रस्ट का नाम
---------	---------------

1	अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट
2.	इनरेका संस्था डॉ. विनोदकुमार एम. कौशिक, अध्यक्ष, इनरेका संस्थान, इनरेका कॉम्प्लेक्स, राजपिपला रोड, डेडियापाड़ा-393040, जिला नर्मदा ।
3.	गुरुमुखी आदिवासी विकास ट्रस्ट तिलकवा जिला नर्मदा 391120
4	लक्ष्य ट्रस टी, दूसरी मंजिल, आरती कॉम्प्लेक्स, जैन डेरासर के सामने, सामने, हीरवंती चेम्बर्स, करेलीबाग, वडोदरा-18

जिले में एमएसएमई से संबंधित मुद्दे :

(1) कॉर्पोरेट प्रशासन में कमी या सरकार की संचार प्रणाली के कारण सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के बारे में एमएसएमई में सबसे बड़ी समस्या बहुत कम जागरूकता है। विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएं और पैकेज तैयार किए गए हैं, लेकिन अधिकांश उद्यमी इससे अनजान हैं।

(2) कुशल मानव संसाधनों की कमी ने भी इस क्षेत्र को ध्यान देने योग्य स्तर पर प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप अभी भी बहुत कम है। कारीगर और बुनकर अभी भी नवीनतम डिजाइनों और बाजार के मौजूदा रुझानों से अनजान बने हुए हैं। उन्होंने पुराने डिजाइन वाले उत्पादों का निर्माण जारी रखा जो उपभोक्ता बाजारों में लगातार मांग उत्पन्न करने में विफल रहे। घरेलू इकाई के मालिकों/बुनकरों/कारीगरों और डिजाइनरों/इंजीनियरों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इन छोटी इकाइयों के मालिकों, बुनकरों, डिजाइनरों के साथ काम करने के लिए इंजीनियरों और फैशन डिजाइनरों को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो पारस्परिक रूप से लाभकारी होंगे और इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे। हाल की प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के बारे में सूचना प्रसार, आधुनिक मशीनरी पर साहित्य, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क विवरण, खरीदार आदि एमएसएमई के लिए बहुत आवश्यक कारक हैं,

(3) आमतौर पर एमएसएमई उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान अवधि से संबंधित एक और बड़ी समस्या। ज्यादातर वे भुगतान में देरी और खराब कर्ज का कारण बन रहे हैं, जिससे कार्यशील पूंजी अनुपात में परेशानी होती है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई कम क्रेडिट अवधि और उसकी ओर से ग्राहकों द्वारा देर से भुगतान करने से भी कार्यशील पूंजी में असंतुलन पैदा होता है।

(4) प्रमुख चिंताओं में से एक एमएसएमई के लिए कम ऋण उपलब्धता है। हालांकि, एमएसएमई को ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ तेजी से बढ़ते क्षेत्रों जैसे गृह ऋण, शिक्षा ऋण को समायोजित करने के लिए; एमएसएमई को ऋण का प्रतिशत हिस्सा गिर गया है। को बढ़ाने की सख्त जरूरत है एमएसएमई को वाणिज्यिक बैंक ऋण देने का लक्ष्य 20% वार्षिक वृद्धि से 30% तक है जो एमएसएमई को ऋण सुविधाओं में वृद्धि करेगा।

(5) जिला राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इसलिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को जिले में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए संयुक्त प्रयास करना चाहिए अर्थात् शैक्षिक संस्थान, यह है, कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए पॉलिटेक्निक, उद्यमिता विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम, और युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। बैंकों द्वारा एमएसएमई को जोखिम प्रबंधन और उदार वित्तीय सहायता के लिए आगे आएं।

#####



**DISTRICT INDUSTRIAL POTENTIALITY SURVEY REPORT
WITH DISTRICT DEVELOPMENT PLAN
OF
ASPIRATIONAL DISTRICT NARMADA
2020-21**

Carried out by

**MSME-DEVELOPMENT INSTITUTE
AHMEDABAD**

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

**Harsiddh Chambers, 4th Floor,
Ashram Road, Ahmedabad-380014**

Ph: 079-27543147/27544248

E-mail: dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in

Website: www.msmediaahmedabad.gov.in

FORWARD

The present economy of any developing nation depends upon the prevailing relationship with World Economic Union and globalised economy of the Developed Nation. Presently our economy is still passing through the edge of Developing Nation's concept. To boost the present economy and for achieving projected growth rate, one must raise the growth of the industrialization. Population explosion is one of the major challenge in growth process of the economy at projected rate in all sector mainly agriculture and industries.

In 2006 the Ministry of Panchayati Raj named Narmada one of the country's 250 most backward districts (out of a total of 640). Narmada district is very near to the well industrially developed district like Vadodara and Bharuch where there is good concentration of MSMEs, and many MSMEs are looking for expansion or diversification. To tap these opportunity concentrated efforts need new to put on to attract MSME to put up their second unit in Narmada district which in turn will start the industrial activity. The strength of the district is availability of the labour, who migrates to Vadodara & Bharuch, as well as rail & road connectivity. The processing of forest produce is also a untapped potential in the district.

Appropriate and required data base of resources and infrastructure facilities exist in the district helps for preparing the policies of the Central and State Government aligning for the development and growth of all the sectors of the district in line with State as a whole. Simultaneously, it is also important to raise the efficiency of the local people through skill development training programmes and industrial seminars etc. for enhancing the entrepreneurship and establish new Micro, Small and Medium enterprises. Thus, it would help in gearing up the process of industrialization in the district.

MSME-Development Institute carries out District Industrial Potentiality Survey Report at regular intervals. This DIPS Report contains Resourceful data base on industrial climate, availability of natural resources, infrastructural facilities, skilled man powers, market conditions etc.

Sh. P.N Solanki, IEDS, Dy. Director and Sh. A. J. Parmar, ISS, Asstt. Director has provided useful guidance to Shri P .L. SHAH, Senior Statistical Officer and Shri S. D. Ramavat, Investigator (E/I) of MSME-Development Institute, Ahmedabad has prepared District Industrial Potentiality Survey Report of Narmada district by using various vital and useful statistics and information collected from the various State Government Departments and agencies.

I extremely feel that it will be definitely useful immensely to the concerned entrepreneurs and various agencies. I extend my heartily thanks to all the State Government Departments and agencies etc., who have extended their kind co-operation in the preparation of this Report.

AHMEDABAD
30.06.2021


(VIKAS GUPTA)
Jt. Director & HoO

C O N T E N T S

CHAPTER No.	NAME OF THE CHAPTER (s)	PAGE NO.
1.	Executive Summary Introduction	01
2.	INTRODUCTION	02
3.	DISTRICT AT A GLANCE	03-05
4.	ANALYSIS OF RESOURCES	06-19
5.	AVAILABLE INFRASTRUCTURE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT	20-32
6.	PRESENT INDUSTRIAL SCENARIO	33-34
7.	PROSPECTS OF NEW MSMEs/INDUSTRIAL DEVELOPMENT	35-38
8.	Schemes and Intervention	39-42
9.	SELF - RELIANT INDIA MOVEMENT UNDER FIVE PILLARS OF ATMANIRBHAR BHARAT	43-44
10.	DISTRICT INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLAN	45
11.	WHOM TO CONTACT AND FOR WHAT ?	46-47
12.	SUMMARY AND CONCLUSION	48
13	LIST OF RESOURCES IN THE DISTRICT	49-51

CHAPTER : 1

Executive summary

The Narmada district is one of the identified district as well as Aspiration district of the Country. The district's major land is the reserved forest, amounting more than 45% and having major population of schedule tribes. Since the forest is reserved, no industrial activities are permitted. Hence, the districts do not have major concentration of industrial establishment including MSMEs. The major economic activities of the district is a farming Major crops is Banana fruit apart from Paddy & Cereal, along with other agro produce.

Presently the Banana, only being sold by the farmers but left out like Banana stem is a major source for the production of products like fiber, SAP water and left out material which is very good absorbent and can be use to manufacture sanitary napkin and if banana stem is made use can turn around the industrial picture of the district and can be boost economical activities of this Aspiration district.

Major land mark of the district are Sardar Sarovar Project – the Narmada Dam and Statue of Unity which is the Tourist destination. To cater the tourism industries, MSMEs can be setup for products/servicelike food, garmenting manufacturing, linen, textile, laundry etc. at and around the Narmada Dam site and in **vicinity** of Statue of Unity.

Narmada district very near to the well industrially developed district like Vadodara and Bharuch where there is good concentration of MSMEs, and many MSMEs their are looking for expansion or diversification. To tap these opportunity concentrated efforts need new to put on to attract MSME to put up their second unit in Narmada district which in turn will start the industrial activity. The strength of the district is availability of the labour, who migrates to Vadodara & Bharuch, and well rail & road connectivity. The processing of forest produce is also a untapped potential in the district.

CHAPTER : 2

INTRODUCTION

The District Industrial Potential Survey Report (DIPS) of Aspirational District -NARMADA WITH DISTRICT INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLAN:2020-21 has been prepared in line with the concept of "ATMANIRBHAR BHARAT" by compiling the available data and information on various resources and infrastructure collected from the different departments of Government of Gujarat working in the district for supporting and strengthening the economic growth of the district.

METHODOLOGY:

The methodology adopted for the survey reports includes desk survey, documentation of data, reports received from various departments and institutions. Derivations and compilations included in this Report through the data collected from various State Government Offices, Local Bodies etc. situated in the district by giving concurrent weightage to the "Secondary" as well as "Primary" data and information about important variants like local markets, demand, agricultural and industrial operations and financial system etc..

OBJECTIVES:

The main objective of the District Industrial Potential Survey Report (DIPS) is to find out the possibilities of establishing and developing new manufacturing units on the basis of local resources and demand in the district during the coming years. To full fill these objectives, correct estimates of available raw materials, natural resources, infrastructure, monetary assistance to the economic sector, industrial policies and programs need significant importance. The problems of present SME sector have been discussed in the report so that the new comers can overcome it and succeed to achieve the targeted rate of growth. The report is techno-economic in nature rather than a mere statistical representation. It will be a focused guide and will be given due publicity to attract the entrepreneurs of the district.

SCOPE:

This Report is prepared with a view to achieve comparatively higher industrial growth rate. It has focused over the problems of the industrial sector and courteous endeavors have been put forth to provide information of the Central as well as State governments industrial policies and programs to overcome the problems and aims to achieve the targeted industrial growth rate in the coming years.

CHAPTER : 3

DISTRICT AT A GLANCE

(in line with the concept of "ATMANIRBHAR BHARAT")

PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES:

Narmada district is located in the southern part of Gujarat. The district shares the border with the State of Maharashtra and bounded with Surat in the South, Vadodara in the North and Bharuch in the West.

Rajpipla located in Nandod taluka is the district head quarter for the Government administration with other taluka namely Dediapada, Sagbara and there are total **5 taluka, 5 towns and 615 villages** in the district. Rajpipla town is the main industrial town in the district. Focused industrial Sector for the further potential of investments is Textile, Agro Food Industries and Chemicals, Cold Storage, Hotels and Herbaceuticals.

District at a Glance :

S. No.	Particulars	Unit	Statistics
1	Geographical features		
(A)	Geographical Data		
	i) Latitude	North	21.24' to 22.0'
	ii) Longitude	East	72.4' to 73.15'
	iii) Geographical Area	Hectares	2,75,536
(B)	Administrative Units		
	i) Sub Divisions	Nos.	--
	ii) Tehsils	Nos.	05
	iii) Sub-Tehsil	Nos.	0
	iv) Patwari Circle	Nos.	0
	v) Panchayat Simitis	Nos.	18
	vi) Nagar Nigam	Nos.	0
	vii) Nagar Palika	Nos.	05
	viii) Gram Panchayats	Nos.	222
	xi) Revenue Villages	Nos.	615
	x) Assembly Area	Nos.	2
2.	Population		
(A)	Sex-wise		
	i) Male	Nos.	3,01,086
	ii) Female	Nos.	2,89,211
	Total :		5,90,297
(B)	Rural Population	Nos.	5,28,425
3.	Agriculture		
A.	Land utilization		
	i) Total Area	Hectare	2,91,023
	ii) Forest cover	"	1,14,709
	iii) Fallow Land	"	7,600
	v) Cultivable Waste Land	"	5,400
	vi) NET area sown	"	1,13,000
4.	Forest	"	
	(i) Forest	Hectares	1,14,709

5.	Livestock & Poultry		
A.	Cattle	Nos.	2,53,671
	i) Cows	Nos.	1,74,657
	ii) Buffaloes	Nos.	79,014
B.	Other Livestock		
	i) Goats	Nos.	79,827
	ii) Pigs	Nos.	183
	iii) Dogs & Bitches	Nos.	367
	iv) Railways		
	i) Length of rail line	Kms.	18
	V) Roads		
	(a) National Highway	Kms.	92.00
	(b) State Highway	Kms.	286.60
	(c) Main District Highway	Kms.	145.30
	(d) Other district & Rural	Kms.	235.38
	(e) Rural road/Agriculture Marketing Board Roads	Kms.	1308.30
	(f) Kachacha Road	Kms.	139.00
	(VI) Communication		
	(a) Telephone connection	Nos.	4435
	(b) Post Offices	Nos.	150
	(c) Telephone Centre	Nos.	03
	(d) Density of Telephone	Nos./1000 person	70
	(e) Density of Telephone	No. per KM	17
	(VII) Public Health		
	(a) Allopathic Hospital	No.	18
	(b) Beds in Allopathic Hospitals	No.	595
	(C) Ayurvedic Hospital	No.	NA
	(d) Beds in Ayurvedic Hospital	No.	NA
	(e) Unani Hospitals	No.	NA
	(f) Community health centers	No.	04
	(g) Primary health centers	No.	28
	(h) Dispensaries	No.	NA
	(i) Sub Health Centers	No.	134
	(j) Private hospitals	No.	20
	(VII) Banking Commercial		
	(a) Commercial bank	Nos.	38
	(b) Rural Bank Products	Nos.	07
	(c) Co-Operative Bank Products	Nos.	15
	(d) PLDB Branches	Nos.	03
	(e) Pvt. Banks	Nos.	10
	(IX) Education		
	(a) Primary Schools	Nos.	731
	(b) Middle Schools	Nos.	---
	(c) Secondary & Higher Secondary Schools	Nos.	130
	(d) Colleges	Nos.	05
	€ Technical University	Nos.	0

Nos. of MSMEs registered in Udyog Aadhaar Memorandum (As on 31.03.2021)

Enterprises including (Manufacturing & Service Sector)	No. of Registered units
Micro	497
Small	82
Medium	11
TOTAL	590

**Nos. of MSMEs registered in Udyam Registration Certificate
(As on 31.03.2021)**

Enterprises including (Manufacturing & Service Sector)	No. of Registered units
Micro	272
Small	10
Medium	0
TOTAL	282

CHAPTER : 4

ANALYSIS OF RESOURCES

Social, economic and industrial growth of any district obviously depends upon the availability of natural as well as skilled human resources. Classification of these resources can be done as under.

(A) Human Resources:

It seeks greater importance in achieving consistent and targeted growth rate in every sector of the economy. Hence, it is divided mainly in two parts namely skilled and unskilled.

Labour force is deemed to be a main key of economy. Availability of labour and high productivity can heavily contribute to the achievements of targeted growth. Labour force is spread over of the district. Available skilled labour is nearly 34.28 % to the total human resources; of which 29.16% are engaged in agriculture and main labourers 22.55 % are engaged in the various sectors of the district. According to Census main characteristics of availability of resources are as given in the table as below.

1. Population:

Description	Details	Gujarat State	Narmada District
Number of Villages	Total	18,225	609
	Inhabited	17,843	558
	Uninhabited	382	51
Number of Towns	Statutory	195	1
	Census	153	4
	Total	348	5
Number of Households	Normal	1,22,48,428	1,20,951
	Institutional	36,925	461
Population Total	Persons	6,04,39,692	5,90,297
	Male	3,14,91,260	3,01,086
	Female	2,89,48,432	2,89,211
Rural	Persons	3,46,94,609	5,28,425
	Male	1,77,99,159	2,69,408
	Female	1,68,95,450	2,59,017
Urban	Persons	2,57,45,083	61,872
	Male	1,36,92,101	31,678
	Female	1,20,52,982	30,194

Description	Details	Gujarat State			Narmada District
Percentage Urban Population		42.60			10.48
Decadal Population Growth 2001-2011		Number	%	Number	%
	Persons	97,68,675	19.27862	5,90,297	14.80
	Male	51,05,683	19.35028	3,01,086	14.10
	Female	46,62,992	19.20077	2,89,211	15.50
Area (in sq Km.)		1,96,244			2,817
Density of Population (Persons per sq Km.)		308			210
Sex Ratio (Number of females per 1000 males)	Total	919			961
	Rural	949			961
	Urban	880			953
Literates		Number	%	Number	%
	Persons	4,10,93,358	78.03	3,70,336	62.73
	Male	2,34,74,873	85.75	3,21,677	54.49
	Female	1,76,18,485	69.68	48,659	08.24
Scheduled Castes	Persons	40,74,447	6.74	8,733	01.48
	Male	21,10,331	6.70	4,465	00.76
	Female	19,64,116	6.78	4,268	00.72
Scheduled Tribes	Persons	89,17,174	14.75	4,81,392	81.55
	Male	45,01,389	14.29	2,44,524	41.42
	Female	44,15,785	15.25	2,36,868	40.13

2. Occupational Pattern of Population:

There are different patterns of available labour force which contributes in the progress of economy of the district. Nearly 31.36 % of the total population is available labour force. According to different pattern of profession of available labour force is divided among the agricultural, industrial and other semi skilled labour.

It can be shown in the Table shown below.

Description	Details	Gujarat State			Narmada District
Category of Workers (Main & Marginal)	Persons	54,47,500	22.00	56,266	09.53
(i) Cultivators	Male	42,44,449	23.58	46,192	08.82
	Female	12,03,051	17.78	10,074	01.71
(ii)Agricultural Labourers	Persons	68,39,415	27.61	1,03,360	17.51
	Male	36,49,591	20.27	68,519	11.61
	Female	31,89,824	47.14	34,841	05.90
(iii)Workers in household industry	Persons	3,43,999	01.39	1,580	00.27
	Male	2,10,561	1.17	1,159	00.20
	Female	1,33,438	1.97	421	00.07
(iv) Other Workers	Persons	1,21,36,833	49.00	32,710	05.54
	Male	98,96,313	54.98	25,646	04.34
	Female	22,40,520	33.11	7,064	01.20

Sr. No.	Description	Population	Percentage
1.	Cultivators	62,823	7.30
2.	Agriculture labours	1,88,030	21.86
3.	Household enterprise labours	2,594	0.30
4.	Other labours	16,297	1.90
5.	Total Labour Force Population	2,69,744	31.36
6.	Main Labourers	1,93,916	22.55
7.	Marginal labourers	1,00,897	11.73
8.	Unproductive population	2,95,502	34.36
	Total population	8,60,059	100.00

(B) Material/Physical Resources:

Industrial growth can be maximized by making the rational usage of the available various resources like technical knowhow, finance, productivity etc. at the proper time in ample quantity.

(1) Cropping Pattern:

The net cultivated area is 1,25,300 hectares in the district. Paddy, wheat, bajra, tur, tobacco, cotton, mustard and fennel are the main crops while potato, banana and lemon are also grown in the district.

Production of various crops grown in the District during the year 2019-20 is as under:

Sl. No.	Name of crop	Area in Hectors	Production (in MT)
1	Cotton	46884	37971.82
2	Banana	9240	662323.20
3	Gram	1087	991.02
4	Tur	22628	27354.99
5	Maize	4803	8743.54
6	Urad	809	817.41
7	Soyabean	1833	2680.95

Agriculture :

Cultivation of various crops in all seasons is carried out through Narmada canal irrigation in the district. Average rainfall is 1100 mm. in Narmada. Banana is the main fruit in the district. Wheat, paddy, Makka, Sugar cane and bajra are the major food crops, while Cotton, Ground nut, castor, and soyabean are the major commercial crops grown in the district. Banana is major crop in plantation. Hence, there exists huge potential for establishing new fruit processing industry in the district. Narmada houses Herbal Botanical Garden, consisting of almost 70 species of herbal plants, which are used for the ayurvedic and natural therapy treatment.

(2) Size of Land Holding

Description of land utilization is given as below:-

Sr. No.	Type of land	Hector
1.	Cultivable land	125300
2.	Permanent Pasture Land	1761
3.	Non agricultural use	31321
4.	Current Fallow land	5973
5.	Forest	114709
6.	Fallow land	7600
7.	Cultivable area for more than once	8755
8.	Net Area Sawn	113000
9.	Cultivable Waste	5400
10.	Grazing Land	9,584

(3) Agricultural Marketing:

Gujarat State Agricultural Marketing Board has established APMC Markets in Selemba, Rajpipla, Dediypada and Tilakvada taluka in the district.

The details of APMC is as Under:

Sl. No.	Type of Market	No.
1	No. of Market Committees	05
2	No. of Main Yards	05
3	No. of Sub-Market Yards	02

Present Development of Agro-based Industries:

Honey production, Small shops of Banana chips by farmers, Fertilizer shops, and small equipment shops for cultivation.

(4) Irrigation Facilities:

Water Resource projects can be classified into three categories (a) Major irrigation projects where culturable command area is more than 10000 hector, (b) Medium irrigation projects where culturable command area is between 2000 to 10000 hector and, (c) Minor irrigation projects where culturable command area is below 2000 hector. The minor irrigation assumes greater importance for sustainable development of agriculture sector in the district. The Monetary Institutional activities are to be emphasized for bank financing schemes for ground water exploitation, water lifting devices, lift irrigation and micro irrigation schemes. The ground water potential of the district is as under :

Sl.No.	Name of Taluka	Ponds	Canals	Others (Check dams)
1	Nadod	84	-	95
2	Garudeshwar	42	991	142
3	Tilakwada	50	-	73
4	Dediapada	109	90	242
5	Sagbara	80	250	210
	TOTAL	365	1331	762

(Source: Ex. Engineer, Panchayat Irrigation Division, Rajpipla)

Garudeshwar Weir :

The construction of Garudeshwar Weir across the river Narmada, with a cost of Rs. 322.47 crore is under progress at about 12 km. downstream of Sardar Sarovar Dam. Upto October-2020, excavation is 10.833 LCM against revised tender quantity of 13.31 LCM and concrete work is 7.70 LCM against revised tender quantity of 8.13 LCM

(5) Horticulture:

Good production of spices, fruits and vegetables is taken in horticulture during the year in the district. Mangoes, banana, chiku, and kharek are the main fruit. Whereas, onion, potato and guwar are the main vegetables. And, guwar, papdi, parwal patal etc. are produced at satisfactory level in the district. Hara dhania, garlic, chili and turmeric are produced in satisfactory quantity in the district under head spices.

Production of various Horticulture Crops in the district is as under: (Area in '000 Hector & Production in '000 Ton)

Sl.No.	Name of Taluka	Fruits		Vegetables	
		Area	Production	Area	Production
1	Nadod	8111	491191	1218	18204
2	Garudeshwar	2195	154430	407	7013
3	Tilakwada	654	12008	338	3224
4	Dediapada	1279	10050	1467	21333
5	Sagbara	1111	13806	918	14239
	TOTAL	13350	681485	4348	64013

Sl.No.	Name of Taluka	Spices		TOTAL	
		Area	Production	Area	Production
1	Nadod	110	2015	9439	511409
2	Garudeshwar	38	273	2640	160716
3	Tilakwada	11	134	1003	15366
4	Dediapada	79	893	2825	32276
5	Sagbara	58	616	2087	28662
	TOTAL	296	3931	17994	748428

Major Food, Commercial and Plantation/ Horticulture Crops:

Wheat, paddy, Makka, Sugar cane and bajra are the major food crops, while Cotton, Ground nut, castor, and soyabean are the major commercial crops grown in the district. Banana is major crop in plantation. Hence, there exists huge potential for establishing new fruit processing industry in the district. Narmada houses Herbal

Botanical Garden, consisting of almost 70 species of herbal plants, which are used for the ayurvedic and natural therapy treatment.

(6) Forest:

The district has a forest area of **1,14,709 hector**. The State Government through Forest Department Authority has undertaken various concrete steps relating to forestry and waste land development. The Forest Department is having network of nurseries in all the taluka for supplying of seeds. There is no production or collection of forest goods in the district.

Talukawise Particulars of Forest Area as on 31/03/2020 is as given below:

Taluka	Total Village	Type of Forest (Area in Hector)			Total Area (Hector)
		Reserve	Unclassified	Protected Forest	
Tilakwada	911	959.08	4.37	0	963.45
Nandod	110	39,380.70	187.53	103.14	39,671.37
Dediyapada	97	63,776.95	587.20	14.04	64,378.19
Sagbara	92	4079.80	5188.91	10.15	9,278.86
Total	558	1,08,196.53	5,968.01	127.33	1,14,291.87

(7) Fisheries:

Particulars of Fisheries are as given below:

Description	No.
No. of Fish Landing Centers	36
No. of Boats to each fish in the District:	
a) Mechanical Boats	02
b) Non-Mechanical Boats	364
Marine Fishermen	Nil
Inland Water Fishermen	5,188
Active	4,881
No. of Primary Fisheries Co-operative Societies	11
Tribal Area	10
Non-Tribal Area	01

No. of membership of Co-operative Societies	2673
a) Tribal Area	2537
b) Non-Tribal Area	136
Share Money deposited by the members	Rs. 89656/-
No. of Fish based Industries functioning in the District	NIL

Particulars of Reservoir/Pond Fisheries are as given below:

Particulars	Type of Reservoir		
	Small	Medium	Large
No.	2	1	0
Hector	345.82	3,677.00	0

• **Elaborate note on Fisheries development in Narmada district :**

Development in the fisheries sector in the District is on going. The people of the district are small land holders so the cultural and captured fisheries are restricted to the local level Demand and Supply purpose only. Slowly the cooperative societies are taking advantages of Government BLUE Revolution Scheme and have installed Aged in the reservoir.

• **Views about the promotion of fish based industries in Narmada District:**

A large water body of Sardar Sarovar is not fully accessed for the fisheries purpose. If the area is given on lease so the large number of fishermen will be benefited by it as well as revenue will be generated. Narmada River is famous for Hilsa and Giant prawn. Fisheries. Hatchery production of these species will minimize the load on nature.

• **Fishing nets used for fishing :**

•

Gill Net : 1092

Cast Net: 600

Varieties of Fish found in the District:

Catla, Rohu, Mrigal, Calabasu, Eel, Prawn, Channa spp., Hilsa etc.

(Source: O\o Superintendent Fisheries, Rajpipla.)

(8) Live Stock Resources:

Description of various livestock in the district is as given below:

Sr. No.	Type of Live stock	Total Animal
1.	Cow	174657
2.	Buffalo	79014
3.	Ships	542
4.	Goats	79827
5.	Horses and Tattus	69
6.	Pigs	183
7.	Others(Donkeys etc.	974
	TOTAL	335266

Source: Livestock Census, 2019, Narmada.

Dairy Development:

The Dairy Development Programme seeks vital significance as a supplementary source of additional income generation in terms of allied activities in the agriculture sector for bringing improvement of living standards of small and marginal farmers and landless labourers of the district.

The talukawise details of Milk co-operative Societies in the district is as under:

Sl.No.	Name of Taluka	Milk co-operative Societies (Nos.)	Milk Supplying Members.	Yearly Collection of Milk(in Ton)
1	Nadod	103	5216	48.41
2	Garudeshwar	54	2784	25.38
3	Tilakwada	68	3548	60.52
4	Dediapada	94	3687	39.96
5	Sagbara	76	3854	30.40
	TOTAL	935	19089	204.67

(9) Mineral Resources:

Grewal, Bentonite, chuno Stone, Black trap, Moram, Common sand and Common Clay are the minor minerals available in the district. There are 20 leased quarries for Black Trap are operating in the district.

Statistics of the various Major & Minor Minerals available in the district during the Year 2019-20 is as under :

Sr. No	Major Minerals	Production (MT)	Royalty (Rs.in '000)
1.	Bauxite	0	0
2.	Quartz	0	0
	Minor Minerals		
1.	Black Trap	64824	241928 68
2.	Common Sand	42925	193100 0
3.	Common Clay	65161	386900
	TOTAL	752226	43856708

Source: Directorate of Geology and Mining, Narmada.

(10) Tourism:

Tourism is now much developing in Narmada District: Sardar Sarovar Dam & Statue of Unity are most popular Tourism places in in Narmada District.

• SARDAR SAROVAR DAM :

The Sardar Sarovar Dam is a concrete gravity dam built on the Narmada river in Navagam near Kevadiya, Narmada District, Gujarat in India. Four Indian states, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, receive water and electricity supply from the dam.

Height: 163 m

Opened: 17 September 2017

Catchment area: 88,000 km²

Surface area: 375.3 km²

Construction began: April 1987

Owners: Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan



- The Statue of Unity:

The **Statue of Unity** is a colossal statue of Indian statesman and independence activist Vallabhbhai Patel (1875–1950), who was the first Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India and an adherent of Mahatma Gandhi during the nonviolent Indian Independence movement. Patel was highly respected for his leadership in uniting 562 princely states of India with a major part of the former British Raj to form the single Union of India. The statue is located in the state

of Gujarat, India. It is the world's tallest statue with a height of 182 metres (597 feet). It is located on the Narmada River in the Kevadiya colony, facing the Sardar Sarovar Dam 100 kilometers (62 mi) southeast of the city of Vadodara^[4] and 150 kilometers (93 mi) from Surat. Kevadia railway station is located at a distance of just 5 kilometers from *Statue of Unity*.

The total height of the structure is 240 m (790 ft), with a base of 58 m (190 ft) and the statue measuring 182 m (597 ft). The height of 182 metres was specifically chosen to match the number of seats in the Gujarat Legislative Assembly.

Features :

The *Statue of Unity* is the world's tallest statue at 182 metres (597 ft). It rises 54 metres (177 ft) higher than the previous record holder, the Spring Temple Buddha in China's Henan province. The previous tallest statue in India was the 41 m (135 ft) tall statue of Lord Hanuman at the Paritala Anjaneya Temple near Vijayawada in the state of Andhra Pradesh. The statue can be seen within a 7 km (4.3 mi) radius.

The monument is constructed on a river island named Sadhu Bet, 3.2 km (2.0 mi) away from and facing the Narmada Dam downstream. The statue and its surroundings occupy more than 2 hectares (4.9 acres), and are surrounded by a 12 km (7.5 mi) long artificial lake formed by the Garudeshwar weir downstream on the Narmada river.

The statue is divided into five zones of which only three are accessible to the public. From its base to the level of Patel's shins is the first zone which has three levels and includes the exhibition area, mezzanine and roof. The first zone also contains a memorial garden and a museum. The second zone reaches up to Patel's thighs, while the third extends up to the viewing gallery at a height of 153 metres. The fourth zone is the maintenance area while the final zone comprises the head and shoulders of the statue.

The museum in the first zone catalogues the life of Sardar Patel and his contributions. An adjoining audio-visual gallery provides a 15-minute long presentation on Patel and also describes the tribal culture of the state. The concrete towers which form the statue's legs contain two elevators each. Each lift can carry 26 people at a time to the viewing gallery in just over 30 seconds. The gallery is located at a height of 153 metres (502 ft) and can hold up to 200 people.

Shri Narendra Modi, then serving as the Chief Minister of Gujarat, laid the statue's foundation stone on 31 October 2013, the 138th anniversary of Patel's birth.

Construction of the monument was completed in mid-October 2018; and the inaugural ceremony was held on 31 October 2018 (143rd birth anniversary of Vallabhbhai Patel), and was presided over by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. The statue has been described as a tribute to Indian engineering skills.

The daily average tourist footfall at *Statue of Unity* during November 2019 reached 15,036, outpacing the Statue of Liberty (which attracts around 10,000 daily visitors on average). It has been included in the Shanghai Cooperation Organisation's '8

Wonders of SCO' list. In its first year of operation, the *Statue of Unity* attracted 29 lakh (2,900,000) visitors and collected ₹82 crore in ticket revenue.^[49] By 15 March 2021, 50 lakh (5,000,000) tourists visited

Narmada Tent City :



Narmada Tent City at the Kevadiya is the fastest way to ensure the ease with infrastructure at the site for the tourist. The tent city was inaugurated on October 31, 2018, and it provides the mesmerizing and magnificent view as it is located just beside the Statue of Unity. It does not only provide the place to stay, but it will also offer water sports, adventure activities, and ecotourism.

THE LUXURIOUS NATURE RETRET :

Tent City Narmada is beautifully placed beneath the shadow of the Statue of Unity, World' Tallest Statue amid the picturesque backdrop of Sardar Sarovar Dam and surrounding natural environs. The Luxurious Nature Resort is a perfect getaway for the urban travelers for close-to-nature experience, away from the fast-paced city life, in the middle of rolling hills, lakes, wooded areas and pollution-free air. The Tent Nestlings at Tent City Narmada are luxurious and well-appointed, where five-star food complements the five-star accommodation. There is a choice of packages, starting from quick 1-day getaways to lazy 2-day escapes from the city. For weekends, bunched holidays, occasions, educational trips, or corporate outings, Tent City Narmada is the perfect nature retreat. The Resort has three exciting accommodation options to suit requirements of all types of tourists - Luxury Tents, Deluxe Tents and Standard Tents, well-equipped with modern amenities.

The Valley of Flowers :



The Valley of Flowers (also known as Bharat Van), is spread across 24 acres of land and is a haven for colourful flowering plants along the bank of river Narmada.

The Valley of Flower began with 48,000 plants in 2016 and has now reached up to 22,00,000 plants. Besides the parks, several photo booths and selfie points have been developed to take back fond memories of the visit. The spot resembles a rainbow of flowers setup on earth.

More than 300 types of flowers are grown in this garden. A right blend of ornamental flowers, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers are planted along with various shades of foliage, which forms the green cover in this area. The amalgamation of these species makes this small area enchanting, flamboyant and intriguing. The picturesque site and an enthralling view of the Statue of Unity certainly captivate the visitors always. This vibrant landscape is also a site for a charismatic flower show every winters.

CHAPTER : 5

AVAILABLE INFRASTRUCTURE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT.

Providing basic infrastructure facilities by the State Government and local authorities is a pre-requisite for speedy economic growth of the district. Such facilities are extensive transportation infrastructure, better communication network, good post & telegraph services, broader banking and financial system, higher educational system and good health services etc. Moreover, easy and cost effective availability of raw materials in huge quantity, technically sound and skilled man power hefty distribution system for the sale of finished goods and services, heavy machinery, constant electricity power and fuel arrangement are significant factors for achieving high industrial growth.

(A) PHYSICAL DIMENSION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES:

(1) Availability of land for establishing various industries :

Availability of vacant plot of land in ample quantity should be easily available to the entrepreneurs. There should be balanced economic growth of the agricultural as well as industrial sectors in the district. Enough land is available for Industrial Develop in the District'

(2) Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC):

Rajpipla of Nandod taluka is the main Industrial Center with GIDC estates in Narmada district. Moreover, in Sagbara, Dediapada and Tilakwada taluka the GIDC acquired land for setting up industrial estates. GIDC helps new as well as existing entrepreneurs for procuring industrial plots and getting other infrastructural and financial assistance from the various banks and institutions. Thus, role of the GIDC seeks greater significant in developing balanced industrial growth in the district.

Industrial Estates situated in various Taluka are described as below:

Sl. No.	Name of Taluka	Name of Industrial Area	Total Area Acquired (R.A)	No. of Sheds	No. Sheds Allotted	Vacant Sheds
1	Nandod	Rajpipla	04	8	8	-
2	Sagbara	Sagbara	23	0	0	-
3	Dediapada	Dediapada	57	12	12	-
4	Tilakwada	Tilakwada	02	0	0	-
5	Garudeshwar	Garudeshwar	10	0	0	-
		TOTAL :	96	20	20	-

3. Water Facility for the Industrial Units:

Water supply for the industrial purposes in the district can be obtained from three main sources like Gujarat Water Supply and Sewerage Board, irrigation canal and Sardar Sarovar Project.

Sardar Sarovar Project:

The project envisages supply of water for drinking purposes, irrigation and industrial use. Water is made available for the industrial use through the branch canals laid down in the different talukas spread over 3.65 km. Wadia, the branch canal supplies water to Narmada district starting from Nandod and end point at Koliary.

(3) POWER:

Electricity Facility:

Narmada hydropower Project having capacity of 1450 Mega Watt at Kevadiya is functioning at present. Under which at River Bed Unit with 1200 Mega Watt was established in February, 2005 at the cost of Rs. 214.08 Crores. And, another unit with capacity of 250 Mega Watt was established in December, 2004 at Kanal Head in Kevadiya also functioning in the district.

A substation of 132 KV is present in Tilakwada connected with Jambuva in Vadodara district.

Description of power stations situated in various talukas is as given below:

Sr. No.	Name of Sub Station	Taluka	Type of Sub Stn.	Capacity in MVA
1	132 KV Tilakwada	Tilakvada	132/66	10
2	66 KV Gaudeshwar	Tilakvada & Nandod	66/11	10
3	66 KV Rajpipla	Nandod	66/11	30
4	66 KV Bhacharvada	Nandod	66/11	20
5	66 KV Pratapnagar	Nandod	66/11	20
6	66 KV Rajpardi	Zagadia	66/11	20
7	66 KV Bhalod	Zagadia	66/11	10
8	66 KV Panetha	Zagadia	66/11	20
9	66KV Dediapada	Dediapada	66/11	10
10	66 KV Chikda	Dediapada	66/11	05
11	66 KV Sagbara	Sagbara	66/11	10
12	66 KV Amadala	Nandod	66/11	15
13	66 KV Anijara	Nandod	66/11	30
14	66 KV Rajuwadiya	Nandod	66/11	30

The Sardar Sarovar dam's main power plant houses six 200 MW Francis pump-turbines to generate electricity and include a pumped-storage capability. Additionally, a power plant on the intake for the main canal contains five 50 MW Kaplan turbine-generators. The total installed capacity of the power facilities is 1,450 MW.

The consumption of Electricity in thr District as under: (2019-20)

Sl. No.	Type of Consumption	Electricity Consumed (in ` Units)
1	Domestic	546.17
2	Commercial	3.03
3	Industrial	240.96
4	Public Street Light	10.00
5	Agricultural Irrigation	628.10
6	Water Tank	131.72
7	Others	13.86
	TOTAL :	1573.49

SOLAR POWER GENERATION :

In 2011, the government of Gujarat announced plans to generate solar power by placing solar panels over the canal, making it beneficial for the surrounding Villages to get power and also help to reduce the evaporation of water. The first phase consists of placing panels along a 25 km length of the canal, with capacity for up to, 25 MW of power.

Gas :

There is one section of gas pipeline passing through the district from Kaalol to Vadodara via Ahmedabad admeasuring about 41.91 km. The proposed length of gas grid is 15 km which is expected to cover the Tarapur Block.

(4) Railway Infrastructure:

There are 4 railway stations in the district. The Gauge conversion work has completed which is connecting the neighboring district with Vadodara and Bharuch It will definitely boost the existing Small and Medium enterprises in the district. It will connect four stations Ankleshwar, Jhagadia, Rajpipla and Vadodara.

(5) Road Infrastructure:

Narmada district is well connected by roads with key industries centers in the State. It is well connected with other important cities like Ahmedabad (195 km), Surat (83 km) and Vadodara (80 km), Gandhinagar (223 km), Jamnagar (467 km), Vapi (150 km), Bhavnagar (357 km) and Ankleshwar (75 km). It is also well connected with major cities of India like Delhi (964 km), Mumbai (419 km), Hyderabad (936 km), Kolkata (1779 km) and Chennai (1493 km).

Description of road is as given below:

Sr. No.	Description of road	Length (In kms.)
1.	National Highways	92.60
2.	State Highways	286.60
3.	District main roads	154.90
4.	Other roads in the district	235.65
5.	Rural Roads	1308.30
6.	Municipality Pucca Road	33.00
	TOTAL	2111.05

Source: Road & Building Department, PWD & District Panchayat.

(6) Public Transport:

State Government Transport Corporation operates buses throughout the district. Moreover, private vehicles like jeep, rickshaws, tractor trolleys, cars, trucks, and motor cycles run over these roads in the district. There are nearly 464758 vehicles registered in RTO of the District. More over motor cycles, scooters, cars, trucks, tractors, trolley, rickshaws etc vehicles are used in large numbers. Model connectivity set up must be established among the SIR, SEZ, Sea ports, Airports etc. to boost the industrialization and overall economic growth. Logistic parks can be erected in the port areas so that requirements for cargo handling and distribution can be managed in more efficient manner.

No. of various types of vehicles registered in RTO as on 31st March, 202:

TOTAL REGISTERED VEHICLE FROM 01-01-2001 TO 31-03-2020		
S. No	Vehicle Class	No Of Vehicle Registered
1	Adapted Vehicle	15
2	Agricultural Tractor	3991
3	Ambulance	49
4	Auxiliary Trailer	2
5	Bus	117
6	Camper Van / Trailer	2
7	Construction Equipment Vehicle	122
8	Crane Mounted Vehicle	8
9	Earth Moving Equipment	3
10	Educational Institution Bus	1
11	e-Rickshaw(P)	2
12	Excavator (Commercial)	13
13	Excavator (NT)	2

14	Fire Fighting Vehicle	2
----	-----------------------	---

-24-

(7) Airport Infrastructure:

There is no airport in the district. The nearest airport situated at Vadodara and Surat.

Seaplane service from Sabarmati riverfront to Statue of Unity has started from Oct 31,2020.

The 19-seater seaplane will be able to accommodate 12 passengers The aerial distance between Ahmedabad and Kevadia is around 200 kilometres. The seaplane is taking about 45 minutes to cover the distance.

(8) Communication Facility:

Telecommunication facility also seeks greater significance in the process of industrialization and economic growth of any district as a modernized equipped infrastructure.

Taiuka wise available infrastructure in the district is under:

Sr. No	Taluka	Name of Exchange	Total Capacity	Working Connection	Waiting List	Per cent of Utilisation %
1	Dediyapada	Navi Bedwan	248	102	0	41.13
2		Pat	248	64	0	25.81
3		Sagbara	496	223	0	44.96
4		Dediyapada	1400	533	0	38.07
5		Selamba	744	481	0	64.65
6	Rajpipla	Bhuchard	248	102	0	41.13
7		Garudeshwar	248	136	0	54.84
8		Jitnagar	248	50	0	20.16
9		Mangrol	248	107	0	43.15
10		Patna	248	84	0	33.87
11		Poicha	248	54	0	21.77
12		Vaghrali	248	64	0	25.81
13		Virpor	248	71	0	28.63
14		Amletha	488	258	0	52.87
15		Gopalpura	488	250	0	51.23
16		K-Colony	2000	311	0	15.55
17		Lachharas	488	321	0	65.78
18		Nikoli	360	222	0	61.67
19		Pratapnagar	744	333	0	44.76
20		Sisodara(Raj)	488	347	0	71.11
		Rajpipla	5000	2415	0	48.30

		TOTAL	15176	6528	0	43.02
--	--	--------------	--------------	-------------	----------	--------------

Bharat Sanchar Nigam Limited, GMTD, Rajpipla.

-25-

(9) NATIONAL CLEAN AIR PROGRAMME (NCAP)

(i) Gradual Shift to cleaner fuels in industries:

The Gujarat State have very good gas dried across the state through which piped in natural gas is being supplied to industrial units. Many units have switched over from fossil fuel (HSD, Coal etc) to natural gas which is a cleaner fuel. Further, the PNG is cheap in compare to fossil fuel. The low cost is the additional factor for the gradual shift to the cleaner fuel by the industries.

(ii) Adoption of solid waste and industrial waste management practices in small scale industries:

The Govt. of Gujarat has established a special organization namely "Gujarat Cleaner Production Center". This institute is establishing Common Effluent Treatment Plant and solid waste site for the waste management. ETP and solid waste sites are already established and operated mainly by industry association in the state of Gujarat.

(iii) Enforcement of environment standards:

The Gujarat Pollution Control Board is enforcing the environment standard, mainly set by Central Pollution Control Board and except red and orange all non polluting industries it has to obtain consent from pollution Control Board before resuming the production.

Further, the Govt. of Gujarat is encouraging the water audit by MSMEs units in order to reduced the use of water by way of subsidizing, the audit fee.

(B) SOCIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES:

1. Entrepreneurship:

In the Five talukas of the district, there are over 590 MSMEs operating at present. Micro Scale industries are mainly engaged in Repairing & Services, Ceramics, Wood Products, Paper & rubber Products etc. Maximum 398 units having investment of Rs. 103.35 Lacs and generating employment to 459 persons are concentrated in Nandod taluka only.

In the reserved forest area, establishment of Industry is not permissible in the District.

Demand based and agro based industries have been mostly developed in the non-farm activities in the district.

-26-

Though the concept of avoiding risk factor for the Governmental regulations and process causes adverse effect and resulted in weakened industrial growth. Industrial Training Institutes, Productivity Development Centers, Small Scale Enterprises Development Institute- Ahmedabad, District Industries Center- Rajpipla and other Non-Governmental organizations must come forward to promote more and more training programmes to increase and motivate the productivity of the labour force available in the district.

2. Marketing Potential:

There are well developed Market Yards in Narmada district for the distribution of the agricultural produces. Farmers can accrue more competitive prices for their produce in these market yards and also in Open market also by selling their produces. There is good infrastructure in the district for the sale of industrial goods and services manufactured and produced. There are number of organized and unorganized marketing arrangements are established in the district.

3. Credit Banks & Lending Agencies:

In conformity with its Corporate Mission to 'promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity NABARD and the Lead Bank-Dena bank has introduced the concept of Potential Linked Credit Plans. The Potential Linked Credit Plans (PLP) for the year 2020-21 is prepared taking into consideration the views and suggestions of the Senior Government Officers of the Line Departments, banks, NGOs, and Progressive Farmers of the district.

The PLP 2020-21 presents the projections of potentials for ground level investments through bank credit after estimating the potential available for exploitation in respect of rural economic activities for overall development of the district taking into account the human and natural resources endowment factors, infrastructure and support services available and likely to be created. The Potential Linked Credit Plans (PLP) Narmada district for the year 2020-21 estimates a total credit of Rs. 48,718.16 Lacs.

Educational and Technical skills Infrastructure:

The no. of education and technical skills Training Institutions as given below:

Sr. No.	Type of Institutions	Number
1	Primary Schools	731
2	Secondary Higher Secondary Schools	130
3	Pharmacy Colleges	01
4	Science College	01
5	Commerce College	01
6	Other Colleges	05

A. No. of educated and unemployed youth registered with the Employment Exchange of the district at Narmada as on 31/03/2020 are as under:

Sr. No.	Standard passed	Male	Female	Total
1	SSC	8600	1018	9618
2	HSC	6984	2833	9817
3	B.Sci.	216	76	292
4	B.Com	235	113	348
5	B.A.	1369	943	2312
6	B.E.	0	0	0
7	Diploma Holders	265	43	308
8	Artisans(Tech), ITI etc.	1428	131	1559
9	Others	7847	2688	10535
	TOTAL	26944	7845	34789

Source: Employment Exchange, Rajpipla.

GROWTH CENTERS:

Growth Centers which helps the administrative and Non-administrative agencies to establish and fasten the industrialization in the district are as under:

(1) MSME-DEVELOPMENT INSTITUTE-AHMEDABAD:

MSME-Development Institute, formerly known as SISI is an organ of the Office of the Development Commissioner, (MSME), New Delhi, in the state of Gujarat. The office of DC (MSME), known as MSME-DO is an apex body & is the nodal agency for formulating, coordinating, monitoring the Policies and Programmes for promotion and development of Micro, Small & Medium Enterprises in the country. The MSME-DI, Ahmedabad provides wide range of Extension Services to the Micro & Small Scale Sector in the state of Gujarat through main Institute at Ahmedabad and two Branch Institutes located at Rajkot & Silvassa.

MSMED ACT 2006:

Vide Gazette notification issued on 2nd Oct., 2006 by GOI, Min. of SSI & Min. of ARI, were merged together and Ministry of MSME was formed.

Package for Promotion of MSMEs declared:

- Credit
- Cluster Based Development
- Technology & Quality Up-gradation Support
- Marketing Support
- Entrepreneurial & Managerial Development
- Empowerment of Women Owned Enterprises
- Strengthening Capability of Associations

Need for more attention

- To Weaker section (SC,ST,PH,WOMEN, MINORITIES & NORTH EASTERN REGION)

-28-

MY MSME MOBILE APP :

My MSME mobile application link launched by M/o MSME on **www.dcmsme.gov.in** for all Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) in India and other stakeholders. This application acts as a source of all information related to MSME's Policies, Registration of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), submission of Online Application for getting Schemes benefit (Credit, Technology, Marketing, Infrastructure, Skill or Policy related), Apply for MSME schemes benefits, Lodge Grievances, MSME Schemes guidelines and Project Profiles, Web links for offices and organizations under Ministry of MSME, MSME Face book Page & MSME Twitter Page etc.

Udyam Registration Certificate :

As per Notification dtd. 26/06/2020 of Udyam Registration, all existing enterprises registered under EM-Part-II or UAM shall re-register again on the Udyam Registration portal : : www.udyamregistration.gov.in on or after the 1st day of July 2020.

Revised MSME Classification is as under:

Composite Criteria: Investment and Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment does not Rs. 1 cr. and Turnover does not Rs.5 cr.	Investment does not Rs. 10 cr. and Turnover does not Rs.50 cr.	Investment does not Rs. 50 cr. and Turnover does not Rs.250 cr.

Becoming a micro, small or medium enterprise.—

- (1) Any person who intends to establish a micro, small or medium enterprise may file Udyam Registration online in the Udyam Registration portal, based on self-declaration with no requirement to upload documents, papers, certificates or proof.
- (2) On registration, an enterprise (referred to as —Udyamll in the Udyam Registration portal) will be assigned a permanent identity number to be known as —Udyam Registration Numberll.
- (3) An e-certificate, namely, —Udyam Registration Certificatell shall be issued on completion of the registration process.

Registration process :

- (1) The form for registration shall be as provided in the Udyam Registration portal.
- (2) There will be no fee for filing Udyam Registration.
- (3) Aadhaar number shall be required for Udyam Registration.
- (4) The Aadhaar number shall be of the proprietor in the case of a proprietorship firm, of the managing partner in the case of a partnership firm and of a karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF).
- (5) In case of a Company or a Limited Liability Partnership or a Cooperative Society or a Society or a Trust, the organization or its authorized signatory shall provide its GSTIN and PAN along with its Aadhaar number.
- (6) In case an enterprise is duly registered as an Udyam with PAN, any deficiency of information for previous years when it did not have PAN shall be filled up on self-declaration basis.
- (7) No enterprise shall file more than one Udyam Registration: Provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Udyam Registration.
- (8) Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act.

Facilitation and grievance redressal of enterprises. :

- (1) The Champions Control Rooms functioning in various institutions and offices of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises including the Development Institutes (MSME-DI) shall act as Single Window Systems for facilitating the registration process and further handholding the micro, small and medium enterprises in all possible manner.
- (2) The District Industries Centres (DICs) will also act as Single Window facilitation Systems in their Districts.
- (3) Any person who is not able to file the Udyam Registration for any reason including for lack of Aadhaar number, may approach any of the above Single Window Systems for Udyam Registration purposes with his Aadhaar enrolment identity slip or copy of Aadhaar enrolment request or bank photo pass book or

voter identity card or passport or driving licence and the Single Window Systems will facilitate the process including getting an Aadhaar number and thereafter in the further process of Udyam Registration.

-30-

(4) In case of any discrepancy or complaint, the General Manager of the District Industries Centre of the concerned District shall undertake an enquiry for verification of the details of Udyam Registration submitted by the enterprise and thereafter forward the matter with necessary remarks to the Director or

Commissioner or Industry Secretary concerned of the State Government who after issuing a notice to the enterprise and after giving an opportunity to present its case and based on the findings, may amend the details or recommend to the Ministry of Micro, Small or Medium Enterprises, Government of India, for cancellation of the Udyam Registration Certificate.

CHAMPION PORTAL :

**CREATION AND HARMONIOUS APPLICATION OF MODERN PROCESSES
FOR INCREASING THE OUTPUT AND NATIONAL STRENGTH.**

Our Small Hands to make you **LARGE!**

Hon'ble PM Shri Narendra Modi Launches CHAMPIONS: Technology Platform to empower MSMEs on 1st June 2020.

The single window system for the MSMEs

It has been felt necessary to put up and promote a unified, empowered, robust, bundled and technology driven platform for helping and promoting the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of the country. As the name suggests it will aim at Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength. Accordingly, the name of the system is CHAMPIONS. This is basically for making the smaller units big by helping and handholding, in particular, by solving their problems and grievances

Three basic objectives of the CHAMPIONS:

- 1) To help the MSMEs in this difficult situation in terms of finance, raw materials, labour, permissions, etc.
- 2) To help the MSMEs capture new opportunities in manufacturing and services sectors.
- 3) To identify the sparks, i.e., the bright MSMEs who can withstand at present and become national and international champions.

Any enterprise can register it's grievance at web portal:

WWW.CHAMPIONS.GOV.IN (E-mail Id: champions@gov.in)

-31-

The detailed of all schemes of MSME are available at web site: dcmsme.gov.in/
<https://msme.gov.in>.

Government of Gujarat, Industries & Mines Department has Notified New Industrial Policy 2020 with the objectives to assist and enhance the competitiveness, development and overall growth of MSMEs in Gujarat.

The Industries Commissionerate is the executive arm of Industries and Mines Department of Government of Gujarat. The office is entrusted with the responsibility of implementation of Industrial Policies of the State and Central Government..

The Industries Commissionerate acts as a catalyst for industrial development in the state by facilitating a conducive environment for investors and bringing about industrial reforms. It offers various incentive schemes and subsidies to the industries for development and upgradation of manufacturing and service enterprises. In case of natural calamities, the office offers various benefits and packages to the industries.

This policy shall be valid for a period of five years from 7th August 2020.

Vision :

To make Gujarat a Global Business Destination for next-generation sustainable manufacturing & service industry driven by state-of-the art infrastructure, employment generation, inclusive & balanced regional development and thereby contribute significantly to "Aatmanirbhar Bharat".

Mission :

To promote entrepreneurship & innovation in the state supported by:

- Inclusive & Balanced regional development
- World class infrastructure
- Competitive fiscal incentives
- Ease of doing business
- Strengthen Integrated Value Chains for an Aatmanibhar Bharat
- Employment generation: Direct & Indirect • Export Competitiveness:
Vocal for Local to become Global
- Effective policy implementation.

Objectives :

- To create an enabling business environment facilitated by a single window system

- To enable industries to set high quality standards and enhance exports
- To have a focused approach for industrially underdeveloped areas & facilitate inclusive & balanced regional growth

-32-

- To promote industries focusing to adopt sustainable, cleaner manufacturing and innovative Industry 4.0 practices
- To strengthen MSMEs and facilitate cluster development
- To strengthen complete value chain across product segment with focus on the objective of an "Atmanirbhar Bharat"
- To encourage R&D, innovation and entrepreneurship
- To provide increased impetus to certain Thrust Sectors with significant potential for employment, exports, investments etc.
- To facilitate growth of Service sector industries in the state
- To facilitate state of the art, sustainable Industrial Infrastructure
- To increase productive employment opportunities in the state

Gujarat Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019:

The main aim of this Act is to facilitate doing business for the MSME sector in the state of Gujarat. An MSME in Gujarat can now start operation upon receipt of an acknowledgement certificate from the state nodal agency by submitting the 'Declaration of Intent'. MSME sector is now exempted from taking various approvals for the first three years. This initiative will smoothen the process of setting up of MSMEs and this in turn will support in employment generation within the State.

The detailed of all schemes of New Industrial Policy 2020 & other Incentives are available at web site : **<https://ic.gujarat.gov.in>**

CHAPTER: 6

PRESENT INDUSTRIAL SCENARIO:

(1) General Industrial Climate:

Normally MSMEs in the district is lagging behind in the point of view of dimensional and motivational strategy. Since, the lack of skilled and well educated people on account of majority belongs to scheduled Tribes the industrial scenario of the district is very much sad. In the reserved forest area, establishment of Industry is not permissible in the District as per Forest policy.

Moreover, entrepreneurs from outside the district are not attracted to establish industries on small and medium scale in the district. In All these factors have slowed down industrial growth in the district.

Therefore, ample care and support are necessary to bring about a change in the perception and practices and make then MSEs successive and improvising the competitiveness for the longer survival through technological transformation ensuring quality and productivity improvisation.

A major strata of population is dependent upon agriculture for their livelihood. Production of banana and cotton are the key horticulture crops in the district. 860 Micro & Small Scale industries (including unregistered in MSME Act) engaged in Repair & Services, Wood products, Paper and Food products are present in the district of which over 300 units are in Nandod taluka.

Nos. of MSMEs registered in Udyog Aadhaar Memorandum (As on 30.06.2020)

Enterprises including (Manufacturing & Service Sector)	No. of Registered units
Micro	497
Small	82
Medium	11
TOTAL	590

Nos. of MSMEs registered in Udyam Registration Certificate (As on 22.06.2021)

Enterprises including (Manufacturing & Service Sector)	No. of Registered units
Micro	272
Small	10

Medium	0
TOTAL	282

-34-

In the five talukas of the Narmada district, there are over 590 Micro & Small Scale & Medium Enterprises operating and generating 990 jobs. Micro Enterprises are mainly engaged in Repairing & Services and Small Scale Enterprises are engaged in Ceramics, Wood Products, and Paper & Rubber Products etc. In Nandod taluka Maximum 398 units having investment of Rs. 103.35 Lacs and generating employment to 459 persons are concentrated.

The industrial scenario of the district is not satisfactory due to lack of awareness on various policies and procedures of the state government as well as Central Govt.

- **Suitable/appropriate Clusters identified for development :-**

Common facility center for banana wafers mfg units under MSE-CDP
Banana Fiber Extraction , bleaching and banana fiber products-
demonstration unit followed by financial assistance for setting up of unit.

The Government of India has launched the '**Transformation of Aspirational Districts**' initiative in January, 2018 with a vision of a New India by 2022 where the focus is to improve India's ranking under Human Development Index, raising living standards of its citizens and ensuring inclusive growth of all.

A total of 115 Aspirational districts have been identified by NITI Aayog based upon composite indicators from Health & Nutrition, Education, Agriculture & Water Resources, Financial Inclusion and Skill Development and Basic Infrastructure which have an impact on Human development Index.

Among them TWO districts namely Narmada and Dahod are the districts of Gujarat.

As per the directives of Secretary (MSME) and the correspondence had with the Chief Secretary, Govt. of Gujarat by the Secretary, MSME, GOI, the following committee has been constituted by Director, MSME-DI, Ahmedabad.

- DIRECTOR, MSME-DI, AHMEDABAD – CHAIRMAN
- STATE DIRECTOR, KVIC, AHMEDABAD – MEMBER
- ZONAL GENERAL MANAGER, NSIC, AHMEDABAD – MEMBER
- GENERAL MANAGER, MSME TOOL ROOM, AHMEDABAD – MEMBER
- MANAGER, COIR BOARD, AHMEDABAD – MEMBER

- REPRESENTATIVES OF OFFICE OF INDUSTRIES COMMISSIONER, GANDHINAGAR-MEMBER
- NODAL OFFICERS OF MSME-DI, AHMEDABAD OF THE RESPECTIVE DISTRICT.

-35-

CHAPTER: 7

PROSPECTS OF NEW MSMEs/INDUSTRIAL DEVELOPMENT:

Narmada district is one of the most backward district having the majority people belongs to Scheduled Caste category. Moreover, being hilly area geographically, remote to the industrialized district and lack of education and skilled labour amongst its aborigine Scheduled Caste population, lack of risk taking nature and entrepreneurship efforts have resulted into slow process of industrialization in the district. Though, Agro based and livestock based as well as Mineral based industries have good scope of development in the district. In addition, many market oriented items for production can also be taken up in the district.

Taking into consideration the available infrastructure facilities and resources in the district and medium & large scale units operating since the last couple of years and huge investment in the projects under the implementation, following industries are considered to have ample potential. Information on potentiality of resource based industries are as follows.

In general following resource based industries have prospects in Narmada District.

(i) Agro and Food based Industries:

Sr. No.	Description
1	Fruit Canning
2	Rice Mill
3	Pickles
4	Fruit Juices & Squashes
5	Cattle Feed
6	Namkeen
7	Biscuits
8	Tuti Fruity from Papaya
9	Mango Juice
10	Mango Powder
11	Groundnut Roasting
12	Spice Powder
13	Mamara/Pova
14	Pop Corn
15	Potato Wafer
16	Banana Wafer
17	Banana Fiber
18	Banana Sap water
19	Sanitary Napkins whitening Banana gar over

	crush as absorbed materials.
--	------------------------------

-36-

(ii)Chemical and allied / Plastics based Industries:

1	PVC Doors & Windows
2	Storage Water Tank
3	Injection Moulded Items
4	LDPE / HDPE Film Bags
5	PVC Reinforced Suction Pipe
6	Polyphone Bags
7	Plastic Toys
8	Surgical and Industrial Gloves
9	Electrical & Electronics Accessories Parts
10	Fishing Nets
11	Nylone Monofilament Yarn
12	Rigid Polyethene Pipes

(iii) Forest and Wood based Industries:

1	Saw Mill
2	Wooden Furniture
3	Handicrafts
4	Herbal Plantation
5	Wooden tools
6	Plywood Chests
8	Mosaic Tiles
9	Emery Powder
10	Carpentry
11	Wooden craft

(iv) Mineral based Industries :

1	Building Bricks
2	Pottery
3	Cement Blocks
4	Flooring Tiles
5	Roofing Tiles

(v) Engineering and Metal Based Industries :

1	Industrial Vales
2	Reduction Gear Boxes
3	Automobile Springs Coal Spring
4	Executive & Conference Chair
5	Pressure Gauges
6	Metallic Filters for Industrial Use
7	Piston Rings
8	Injection Moulding Machine
9	Ball Bearings
10	Refrigeration & Air Conditioning Equipments
11	Dry Cell Batteries & Storage Batteries

(vi) Live Stock and Leather Based Industries:

1	Leather footwear and Leather goods
2	Bone Meal
3	Leather Decorative items
4	Garments and Sports Goods
5	Leather Bags and purse
6	Wood Works
7	Leather Tanning
8	Dairy

(vii) Repairing and Service Enterprises :

1	Xerox Centre
2	Computer Job Work & Training Centre
3	Cyber Café, Network, E-mail Service, Internet Service
4	Mobile Phone Service
5	Automobile Spares, Service and Repairs
6	Video Library
7	Repairing of Electrical & Electronic Equipments
8	Steel Fabrication
9	Electric Motor Repairing
10	Laundry and Dry Cleaning
11	Fast Food and Snack Parlour
12	Ice Cream Parlour
13	Pathology Laboratory

(viii) Textile Industries:

1	Hosiery
2	Grey Cloth Processing
3	Twisting
4	Texturizing
5	Crimping of Yarn
6	Weaving
7	Power Looms
8	Crimping of Yarn
9	Cotton knitted

(ix) Ancillary and Other Miscellaneous.

Sr. No.	Description
1	Hardware items like nuts, bolts, washers, nails etc.
2	Phenyl, tiles, cleaners, acids.
3	Wire ropes & other lifting materials
4	Casting of various qualities.
5	Refractors.
6	Adhesives
7	Sulphur
8	Hydrochloric Acid, Dry chemical powder.
9	Fire Bricks.
10	LPE Hose.
11	Oil & Grease.
12	Expeller
13	Cotton waste.
14	Soap stock.
15	Polythene Bags
16	Tissue papers.
17	Printer cables
18	Electrical Items.

19	M.S. electrodes.
20	Polythene Bags

-39-

CHAPTER: 8

Schemes and Intervention

(I)

(A) Suitable/appropriate Clusters identified for development :-

Common facility center for banana wafers manufacturing units under MSE-CDP
Banana Fiber Extraction , bleaching and banana fiber products- demonstration unit followed by financial assistance for setting up of unit.

Under MSE-CDP :

Demonstration done for the unit of banana fiber extraction, Bee keeping and honey processing unit by KVIC.

Marketing support by participation in National and international exhibition

Mobilized for financial support under MUDRA, PMEGP etc. to existing skilled persons for self employment.

Organized skill development programmes followed by mobilization of financial support under MUDRA, PMEGP etc.

(B) Large/Medium Scale Industries:

Industrial units having investment exceeding Rs. 50 crore in plant and machinery and Turnover of Rs. 250 Cr. (**Composite criteria**) are classified as large industrial units.

An Entrepreneur or a company desirous to set up a large project needs an approval in the form of industrial license from Government of India (GOI) under the provisions of Industries (Development and Regulations) Act, 1951. In July 1991, Government of India liberalized the licensing procedure and exempted almost all the industries from the purview of industrial licensing, except a few industries which are of strategic importance. In the case of setting up of an Export Oriented Unit (EOU) or setting up a project in Special Economic Zone (SEZ), a Letter of Permission (LoP) is required to be obtained from the Development Commissioner of the concerned SEZ. Thus, the procedure for setting up a large industrial unit would be either filing of IEM, obtaining Letter of Intent (LOI)/ Industrial License or obtaining Letter of Permission (LoP) in the case of 100% EOU or SEZ unit.

Particulars of Medium & Large Scale and other industries are as under:

Sl. No.	Name of Unit	Taluka	Production
1	Shree Narmada Sugar Industry Co-op. Socy. Ltd., Dharikheda	Nandod	Sugar

2	Shree G.S.L.(I) Pvt. Ltd., Amletha	Nandod	Yarn
3	Oreva Energy Pvt. Ltd., Karan Dev at Village: Jitnagar	Nandod	Power
4	M\s Amar Carbon & Chemicals, Rajpipla	Nandod	Activated Carbon

-40-

5	M\s Prashant Pharmaceuticals, Rajpipla	Nandod	Ayurvedic Medicines
6	M\s Bhagwatikrupa Marble Industries, Rajpipla	Nandod	Marble cutting & polshing
7	Shram Jyoti Wood Works, Rajpipla	Nandod	Wooden Furniture
8	M\s Mahalaxmi Quarry Works, Vansla	Nandod	Rubber Greet & Kapchi
9	New Snadeep Tyre, Rajpipla	Nandod	Tyre Remolding
10	M\s Kesri Nandan Pipes, Rajpipla	Nandod	HDPE Pipes
11	M. J. Pole Fty., Rajpipla	Nandod	Cement Pipes
12	M\s P. R. Fuel, Dharikheda	Nandod	Collection, Process and Distribution of Agro Waste

(C) List of State and Central PSUs in the Narmada District.

- NIL -

(D) Particulars of Industrial Associations and Chamber of Commerce are as given below:

Sr. No.	Association/Chamber of Commerce	Telephone No.
1	Rajpipla Small Scale & Owners Association P. b. No 42, Plot No.: I/45/1, GICD, Rajpipla (Taluka: Nandod)	02640-220062
2.	The Rajpipla Vividh Vepari Mandal, Parikh Statonery Mart, Station Road, Rajpipala-393145	02640-220677-
3.	Narmada Chamber Of Commerce & Ind., C/O. SHETH & CO. STATION ROAD, RAJPIPLA Rajpipla-393145	02640-220197

(E) The no. of education and technical skills Training Institutions as given below:

Sr. No.	Type of Institutions	Number
1.	Pharmacy Colleges	01
2.	Science College	01
3.	Commerce College	01
4.	Women Polytechnic College	01
5.	ITI	05

-41-

(II)Ongoing Schemes like Industrial Cluster/Design/IPR/GI Tag.

Common facility center for banana wafers manufacturing units under MSE-CDP Banana Fiber Extraction , bleaching and banana fiber products-demonstration unit followed by financial assistance for setting up of unit.

Narmada district has been identified as aspirational district by Govt. of India. One of the potential of establishing cluster under MSE-CDP is based on Banana crop which is being grown in ample quantity. After taking the Banana fruit, Banana stem disposal is one of the problems but it is a very good raw material for:

- 1) Extraction of Banana fiber - used for different Handicraft products. It can be used for blending with textile yarn and can also be used in FRP etc..
- 2) During the extraction of fiber, liquid coming out is known as SAP water which can be used as manure.
- 3) The left out can be dried and used in powder form as absorbent material to manufacture sanitary napkin.

The status of intervention under MSE-CDP in the Aspirational District of Gujarat.

Intervention proposed	Status as on date
Cluster formation for Banana Processing	Due to joint efforts of MSME-DI, Ahmedabad and Horticulture Deptt. Govt of Gujarat, 09 units of banana fiber extraction have been established. More units are under establishment. Once 20 units came up, proposal for CFC to further processing of fiber can be taken up.

(ii) No. of Udyam Registration in the District as on 31/03/2021.

Enterprises including (Manufacturing & Service Sector)	No. of Registered units
---	--------------------------------

Micro	272
Small	10
Medium	0
TOTAL	282

-42-

Growth Trend:

There is a potentiality growth in Agro sector. Agriculture provides the maximum opportunity to generate sustainable livelihood and employment for the villagers in the district.

* Total 590 MSMEs units, engaged in repair & services, wood products, paper and food products etc. are present in the district of which over 400 units are present in Nandod Taluka Industries such as textiles, sugar and chemicals observed major investment and substantial growth during the past Two decades.

* Now a days concept of Eco adventure Tourism is developing the world. The Forest and Environment department of Gujarat Government has selected 6 sites in Narmada district to attract the tourists from out of Gujarat State. The selected sites are Shoolpaneshwar, Kevadia, Vishalkhadi, maal-samot, Zarwani, & Kadia Dungar

* Narmada houses Herbal Botanical Garden, consisting of almost 70 species of herbal plants, which are used for the Ayurvedic and natural therapy of treatment, and also helps in increasing medical value travel in the district.

CHAPTER : 9

Self - Reliant India Movement under Five Pillars of Atmanirbhar Bharat.

SELF-RELIANT INDIA MOVEMENT :

Recently, Hon'ble Prime Minister has announced the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan (or Self-reliant India Mission)' with an economic stimulus package — worth Rs 20 lakh crores aimed towards achieving the mission.

- The announced economic package is 10% of India's Gross Domestic Product (GDP) in 2019-20.
- The amount includes packages already announced at the beginning of the lockdown incorporating measures from the RBI and the payouts under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.
- The package is expected to focus on land, labour, liquidity and laws.

The Mission will be carried out in **two phases:**

Phase 1: It will consider sectors like medical textiles, electronics, plastics and toys where local manufacturing and exports can be promoted.

Phase 2: It will consider products like gems and jewellery, pharma and steel, etc.

Five pillars of a self-reliant India in the District:

- 1)** Economy, which brings in quantum jump and not incremental change
- 2)** Infrastructure, which should become the identity of India
- 3)** System, based on 21st-century technology-driven arrangements
- 4)** Vibrant Demography, which is our source of energy for a self-reliant India and
- 5)** Demand, whereby the strength of our demand and supply chain should be utilized to full capacity.

SWOT ANALYSIS :

Strength : Narmada District is very wealthy having it's Natural Resources. There is a potentiality growth in Agro sector. Agriculture provides the maximum opportunity to generate sustainable livelihood and employment for the villagers in the district.

2) Weakness: Since, the majority people in Narmada district belongs to Scheduled Tribe, there is lack of skilled persons, low literacy rate, forest area and lack of initiate risk to become an entrepreneur are the main cause for not having greater scope for vaporization. Hence, the industrial growth in the district is low in the district in comparison to the other districts of Gujarat state.

-44-

(3) Opportunities: Tourism is now much developing in Narmada District: Sardar Sarovar Dam, Statue of Unity, Tent City and The valley of Flowers are most popular Tourism places in in Narmada District. Nearby people are getting much more employment in this placesof attractions.

(4) Threats: Since, the majority people in Narmada district belongs to Scheduled Tribe, there is lack of skilled persons, low literacy rate, forest area and lack of initiate risk to become an entrepreneur are the main cause for not having greater scope for vaporization. Hence, the industrial growth in the district is found low in the district in comparison to the other districts of Gujarat state

CHAPTER : 10

DISTRICT INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLAN.

UNDER DIFFERENT SCHEMES:

Sl. No.	Development Activity	FUNDING (Rs. In Lacs)			Remarks
		GOI	State Govt.	Others like SPVs etc.	
1	Post COVID 19 Revival Package: Loan Sanction / Disbursement to MSMEs under the package to be reported by Banks. No. of applications received/ approved:4618	2466 Lacs	-	-	
2	Mukhya Mantri Amrutam Scheme No. of Claims: 2942	-	485.62	-	
3	For the planning of Decentralized District	-	987.50	-	
4	Cluster Development Programme	Upto 80% of Max. Cost Rs.20 Cr.	10%	10%	

CHAPTER : 11

WHOM TO CONTACT AND FOR WHAT ?

Following are the brief description of difference agencies for rendering assistance to the entrepreneurs.

Sl.No.	Type of assistance	Name and address of agencies
1.	Udyam Registration Certificate)	District Industries Centre, 2 nd Floor, Jilla Seva Sadan, Rajpipla, Dist. Narmada & MSME-DI, Ahmedabad.
2.	Identification of Project Profiles, techno-economic and managerial consultancy services, market survey and economic survey reports.	MSME-DI, 4 th Floor, Harsiddh Chambers, Ashram Road, Ahmedabad. 380 14.
3.	Land and Industrial shed	GIDC, Plot No:624/B, GIDC, Valia Road, Ankleshwar, Dist. Bharuch
4.	Financial Assistance	Bank of Baroda, (Dist. Lead Bank), Kalia Bhoot Circle, Rajpipla, Dist. Narmada.
5.	For raw materials under Govt. Supply	NSIC, 202-203, Samrudhhi Building, Nr. Old Gujarat High Court, Ahmedabad-380 014
6.	Plant and machinery under hire/purchase basis	NSIC, 202-203, Samrudhhi Building, Nr. Old Gujarat High Court, Ahmedabad-380 014
7.	Power/Electricity	South Gujarat Vijnigam co.Ltd., Tilakwada, Dist. Narmada.
8.	Technical Know-how	MSME-Tool Room, (Indo-German tool Room), Plot No. 5003, Phase IV, GIDC, Vatva, Ahmedabad: 382 445.

9.	Quality & Standard	BIS,Khanpur,Ahmedabad
10.	Marketing/Export Assistance	MSME-DI, 4 th Floor, Harsiddh Chambers, Ashram Road,Ahmedabad.380 14.

-47-

11.	Other Promotional Agencies	<p>1) MSME Commissioner, Block No-1 & 2, Udyog bhavan, Gandhinagar-382 017</p> <p>2)Centre for Entrepreneurship Development (CED) Block No. 1, 9th Floor, Udyog Bhavan, Sector -11 Gandhinagar 382 017</p> <p>3) MSME Tool Room/Indo- German Tool Room (IGTR) Plot No. 5003, Phase-IV GIDC, Vatva, Ahmedabad</p>
-----	----------------------------	---

STEPS TO SET UP A MICRO, SMALL OR MEDIUM ENTERPRISE

The important aspects are as given below:

- (1) Selection of proper Project
- (2) Selection of appropriate Technology & Machinery
- (3) Feasible Planning for getting finance
- (4) Conceptualization of Basic Infrastructure: erecting of factory building, arrangement of necessary connection such as Power, Sewerage and Communication etc., Labour and Personnel, Procurement of Raw Material.
- (5) Filling of Udyam Registration Certificate with respective District Industries Center of the district.
- (6) Sanction of Approvals such Regulatory, Taxation, Environmental clearance in certain products etc.
- (7) Registration of Quality Certification

CHAPTER : 12

Conclusion and way forward

The Narmada district is industrially backward district. The district is blessed with reserved forest and rich agriculture but these resources are almost untapped. The agriculture produce are not being process further which can turn around the economical scenario of the district if done so. The Banana is the major fruit being farmed in more than 10000 hector and only fruit is being sold out and rest of the part of the Banana plant is not being utilised to manufacture: Banana Fibre, from which many products including textile can be produced if further process, SAP water which rich in many minerals is the buy products produced during extraction of Banana Fibre and it is very good liquid manure, after fibre extraction and SAP water the left out of the Banana steam is a very good absorbent and can be used in manufacturing product like sanitary napkin. This only crop have the potential to change the industrial and economical scenario of the district.

The adjoining districts, Bharuch and Vadodara are industrially developed and many industries including MSMEs are looking for either expansion or diversification. Such units can be invited in the Narmada district to start the industrial activity and such units are attracted to the district as it is well connected by Rail & Road with other part of state.

The district is blessed with abundant labours who migrate to Bharuch & Vadodara district and work there in the industrial unit. The experience and the skill available with these labours can also be made use for development of MSMEs in the district.

Under the industrial policy-2020 of Govt. Of Gujarat, various incentives are available in the Talukas of the district.

The district needs the concentrated approached to exploit the available resources and strength of the district to how more and more industrial units in the district to uplift the economic and employment scenario.

CHAPTER : 13

LIST OF RESOURCES IN THE DISTRICT

Detail List of Industries Association.

Particulars of Industrial Associations and Chamber of Commerce are as given below:

Sr. No.	Association/Chamber of Commerce	Telephone No.
1	Rajpipla Small Scale & Owners Association P. b. No 42, Plot No.: I/45/1, GICD, Rajpipla (Taluka: Nandod)	02640-220062
2.	The Rajpipla Vividh Vepari Mandal, Parikh Statonery Mart, Station Road, Rajpipala-393145	02640-220677-
3.	Narmada Chamber Of Commerce & Ind., C/O. SHETH & CO. STATION ROAD, RAJPIPLA Rajpipla-393145	02640-220197

Detailed List of PSU

Sr. No.	Name of Public Sector Unit	Telephone No.
1	Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. (SSNNL) Regd. Office :Block No 12, 1st floor, New Sachivalaya , Gandhinagar Gujarat	E-mail : cio@sardarsarovard am.org Phone : 3220669 (C), 3223518 (MD) , Fax : 3223056 Website: www.sardarsarova rdam.org,

LIST OF NGOS :

Sr. No.	Name of TRUST.
1	AMBEDKAR EDUCATION TRUST
2.	INRECA SANSTHA Dr.Vinodkumar M. Koushik, President, INRECA Sansthan, INRECA Complex, Rajpipla Road, Dediapada-393040, Dist.Narmada.
3.	GURUMUKHI ADIVASI VIKAS TRUST Tilakwada Dist. Narmada 391120
4	Lakshya Trust, second floor, Aarti Complex, Beside Jain Derasar, Opp. Hiravanti Chambers, Karelibaug, Vadodara-18

Issues concerning MSMEs in the District :

- (1) The utmost Problem is very low awareness in MSMEs about government schemes and subsidies because of lack in corporate governance or due to communication system of the government itself. There are lots of incentive schemes and packages especially designed for MSMEs but most of the entrepreneurs remain unaware of it.
- (2) Lack of skilled human resources has also affected the sector at noticeable level. Technology intervention is still very low in the sector. Artisans and weavers still have been remained unaware of latest designs and current market trends. They continued to manufacture products with old designs which fail to generate consistent demand in the consumer markets. There is still huge gap among the household unit owners/weavers/artisans and the designers/engineers. There is immense need to encourage engineers and fashion designers to work out with these small units' owners, weavers, designers which would be mutually beneficial and help revive the sector and make it globally more competitive. Information dissemination about availability of recent technologies, literature on modern machinery, contact details of suppliers of raw materials, buyers etc. are very essential factors for the MSMEs,

- (3) Another major problem related to payment durations normally faced by the MSME entrepreneurs. Mostly they are causing delay in payments and bad debts, which causes trouble in the working capital ratio. Low credit period provided by the suppliers and on other side late payment made by the customers also creates imbalance in the working capital.
- (4) One of the major concerns is low credit availability to the MSMEs. Though, credit to MSMEs fall under the category of priority sector lending, but with the expansion of the priority sector lending to accommodate fast growing areas such as home loans, education loans; the percentage share of credit to MSMEs have been fallen down. There is strong need to increase the

-51-

target of commercial bank lending to MSMEs from 20 % year on year growth to 30% which will enhance the credit facilities to MSMEs.

- (5) The district is one of the most backward districts of the state. Hence, the State Government, Central Government and other stake holders must put joint efforts to improve the infrastructure in the district at all levels i.e. Educational Institutions, it is, Polytechnics to prepare skilled labours, entrepreneurship development training programmes, and increase capabilities of youth to come forward for risk management and liberal financial support to the MSMEs by the bankers.

#####